जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

R.N.I. No. 63177/95 वर्ष:27 अंक: 159 दिनांक:23-05-2022 सोमवार मूल्य : 1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 अहमदाबाद M

आगामी 10 जून को राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान उम्मीदवारों के चयन में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि इन चुनावों में कांग्रेस को अधिकतम नौ सीटें मिल सकती हैं...

कूटनीतिक लिहाज से क्वाड की यह बैठक बेहद उपयोगी है। भारत चीन सीमा विवाद को देखते हुए भारत के लिए क्वाड बेहद उपयोगी मंच है। कूटनीतिक लिहाज से यह बैठक भारत के लिए कितनी उपयोगी है। इसपर रूस-चीन की पैनी नजर क्यों है।

पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने पार्टी छोड़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल

कोलकाता (ईएमएस)। पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। सिंह का तृणमूल में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दक्षिण कोलकाता में उनके कार्यालय में स्वागत किया। तृणमूल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, 'पश्चिम बंगाल भाजपा इकाई के पूर्व उपाध्यक्ष और बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह का अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस परिवार में गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। वह हमारे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में हमसे जुड़े।'

इससे कुछ दिन पहले अर्जुन सिंह ने पार्टी के राज्य नेतृत्व पर ठीक से काम करने की अनुमति नहीं देने के लिए निशाना साधा था। अर्जुन सिंह इस बात से नाराज थे कि केंद्र ने जूट की कीमतों को 6,500 रुपये प्रति क्विंटल करने की अधिसूचना को वापस ले लिया। इसको लेकर वह और अन्य उद्योग हितधारक पिछले कुछ हफ्तों से मांग कर रहे थे।

सूत्रों ने यह भी बताया कि अर्जुन सिंह हाल ही में भाजपा की राज्य इकाई में गुटबाजी को लेकर भाजपा के शीर्ष अधिकारियों से मिलने के लिए दिल्ली गए थे। इस दौरान उन्होंने जूट मिल के मुद्दे को भी उठाया।

बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह पिछले छह महीने से तृणमूल कांग्रेस के साथ संपर्क में थे। सूत्रों ने कहा कि भाजपा ने उन्हें मनाने के कई असफल प्रयास किए।

बैरकपुर सीट से दिनेश त्रिवेदी को टिकट देने के बाद अर्जुन सिंह ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल छोड़ दी थी। उन्होंने त्रिवेदी को हराया, जो इस सीट से दो बार के सांसद थे। सिंह के बेटे पवन सिंह भाटपारा से भाजपा विधायक हैं, और अपने पिता के नक्शेकदम पर चल सकते हैं।

बाबुल सुप्रियो के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी छोड़ने वाले अर्जुन सिंह दूसरे लोकसभा सांसद हैं। वरिष्ठ तृणमूल नेता सुब्रत मुखर्जी के निधन के बाद बालीगंज विधानसभा सीट पर हालिया उपचुनाव में बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीतने में कामयाब रहे।

पूर्वी मेदिनीपुर जिले में बंगाल पुलिस में बरामद किए बम से भरे 15 ड्रम, किए गए निष्क्रिय

कोलकाता (ईएमएस)। पश्चिम बंगाल की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। राज्य के पूर्वी मेदिनीपुर जिले स्थित बक्चा के होगला वन क्षेत्र से शनिवार को मिले बमों को बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया है। ये बम पूर्वी मेदिनीपुर में पुलिस की छापेमारी के दौरान मिले थे। बम मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत यह सूचना बम निरोधक दस्ते को भेजी थी। खबरों के मुताबिक पुलिस ने बम से भरे होने के संदेह में करीब 15 ड्रम बरामद किए थे। बमों की संख्या एक हजार से अधिक बताई जा रही है। इस संबंध में पूर्वी मेदिनीपुर के पुलिस अधीक्षक अमरनाथ ने कहा कि हमें वहां बम होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद हमने सर्च अभियान चलाया और बम के ड्रम बरामद किए। इसके बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाया और उन्हें निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू की।

पुलिस ने इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगटुई नरसंहार के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस को हथियार और बम तलाशी का आदेश दिया था। इसके तहत पुलिस विभिन्न इलाकों में अभियान चला रही है। मालूम हो कि यह पहला मौका नहीं है, जब पश्चिम बंगाल से इस तरह से बम बरामद किए गए हों। इससे पहले बीरभूम जिले में पुलिस ने टीएमसी नेता भादू शेख की हत्या के आरोपी के घर के पास जमीन में दबे क्रूड बम को जब्त किया था। इसके अलावा बीरभूम जिले के रामपुरहाट के मारग्राम में 40 देसी बम मिले थे। इन बमों को 4 बाल्टियों में छिपाकर एक निर्माणाधीन घर के पिछले हिस्से में रखा गया था।

ज्ञानवापी विवाद के बीच क्या कुतुब मीनार परिसर में होगी खुदाई

नई दिल्ली (ईएमएस)। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में पाए गए कथित 'शिवलिंग' के बाद अब कुतुब मीनार को लेकर छिड़े विवाद के बीच इस ऐतिहासिक परिसर में भी खुदाई कर हकीकत जानने की मांग जोर पकड़ने लगी है। हिन्दू संगठनों का कहना है कि परिसर में अनेक मूर्तियां विभिन्न स्थानों पर रखी हुई हैं। बीते दिनों हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इस परिसर के पास हनुमान चालीसा पाठ करके कुतुब मीनार का नाम बदलकर 'विष्णु स्तंभ' रखने की मांग की थी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा कुतुब मीनार परिसर में खुदाई कराई जाएगी, ताकि कुतुब मीनार में मूर्तियों की आइकोनोग्राफी कराई जा सके। दावा है कि संस्कृति विभाग ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि, जब इस दावे की हकीकत जानने की कोशिश की गई तो यह पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद निकला। इस बारे में अभी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग दिल्ली मंडल को खुदाई और अध्ययन के संबंध में संस्कृति मंत्रालय से कोई औपचारिक निर्देश लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों ने परिसर का दौरा जरूर किया था। संस्कृति मंत्रालय के विश्वनसीय सूत्र ने अपना नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर कहा कि इस बारे में साफ कहा कि मीडिया में चल रही इस तरह की खबरें पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृति मंत्रालय की तरफ से किसी भी तरह की खुदाई कराने के कोई आदेश नहीं दिए गए हैं। हालांकि, जब इस दावे की हकीकत जानने की कोशिश की गई तो यह पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद निकला। इस बारे में अभी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग दिल्ली मंडल को खुदाई और अध्ययन के संबंध में संस्कृति मंत्रालय से कोई औपचारिक निर्देश लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों ने परिसर का दौरा जरूर किया था। संस्कृति मंत्रालय के विश्वनसीय सूत्र ने अपना नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर कहा कि इस बारे में साफ कहा कि मीडिया में चल रही इस तरह की खबरें पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृति मंत्रालय की तरफ से किसी भी तरह की खुदाई कराने के कोई आदेश नहीं दिए गए हैं।

के चंद्रशेखर राव ने पंजाब में किसान नेताओं से केंद्र के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखने की अपील की

चंडीगढ़ (ईएमएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पंजाब में किसान नेताओं से केंद्र के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखने की अपील की, जब तक उन्हें फसलों के समर्थन मूल्य पर संवैधानिक गारंटी नहीं मिल जाती। उन्होंने कहा, 'किसान सरकारें बदल सकते हैं।' उन्होंने राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि वह आम आदमी पार्टी जैसे अन्य विपक्षी दलों के साथ शामिल होंगे और समर्थन करेंगे।

प्रमुख किसान नेता राकेश टिकैत भी वहां मौजूद थे। राकेश टिकैत पिछले साल विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के नेताओं में से एक थे। केसीआर ने अपने भाषण की शुरुआत में उनका नाम भी लिया।

उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 600 किसानों के परिवारों को संबोधित किया, श्रद्धांजलि दी और सहानुभूति व्यक्त की। तेलंगाना सरकार ने भी आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों के लिए 3 लाख रूपये के मुआवजे की घोषणा की है।

अपनी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, केसीआर ने कहा कि तेलंगाना के गठन से पहले किसान काफी संकट में थे और हर दिन कई लोग आत्महत्या कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि बिजली बहुत कम या न के बराबर थी, और बहुत सारी समस्याओं का समाधान किसी ने नहीं किया।

उन्होंने कहा, 'तेलंगाना बनने के बाद बिजली की समस्या दूर हो गई। हम 24 घंटे उच्च गुणवत्ता वाली बिजली मुफ्त में मुहैया कराते हैं।' केंद्र पर कटाक्ष करते हुए, उन्होंने दावा किया कि वे तेलंगाना सरकार पर बिजली के मीटर लगाने और मुफ्त में बिजली नहीं देने का दबाव बनाते हैं। उन्होंने कहा, ठवे हमसे पैसे निकालने, किसानों का खून चूसने के लिए कहते हैं। मैंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मीटर लगाने की बजाय वह मरना पसंद करेंगे।'

उन्होंने कहा, ठजब भी कोई राज्य किसानों के लिए कुछ करता है, तो उन्हें यह पसंद नहीं होता है।'

कार्टून कोना

गांव वालों ने थाने में लगा दी आग आरोपियों के घरों पर चला बुलडोजर

नई दिल्ली (ईएमएस)। असम के नागांव में कई लोगों के घरों पर बुलडोजर चल गए। दरअसल यहां एक दिन पहले कुछ लोगों ने थाने में आग लगा दी थी। इसके बाद आरोपियों के घरों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। सलोनाबोरी गांव के लगभग 40 लोगों की भीड़ ने बाताद्रवा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। उनका कहना था कि एक शख्स की पुलिस हिरासत में मौत हो गई है। नागांव जिला प्रशासन ने मौत की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा पुलिस स्टेशन के प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। रविवार सुबह गांव में बुलडोजर पहुंचा और जो लोग थाने में आग लगाने में शामिल थे, उनके घर ढहा दिए गए। असम के नागांव में कई लोगों के घरों पर बुलडोजर चल गए। दरअसल यहां एक दिन पहले कुछ लोगों ने थाने में आग लगा दी थी। इसके बाद आरोपियों के घरों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। सलोनाबोरी गांव के लगभग 40 लोगों की भीड़ ने बाताद्रवा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। उनका कहना था कि एक शख्स की पुलिस हिरासत में मौत हो गई है। नागांव जिला प्रशासन ने मौत की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा पुलिस स्टेशन के प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। रविवार सुबह गांव में बुलडोजर पहुंचा और जो लोग थाने में आग लगाने में शामिल थे, उनके घर ढहा दिए गए।

बिहार- समस्तीपुर में छात्र की मौत पर आक्रोशित छात्रों ने विवि में तोड़फोड़ के बाद फूंकी गाड़ियां

समस्तीपुर (ईएमएस)। बिहार के समस्तीपुर में डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के छात्र की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत के बाद उपचार में लापरवाही का आरोप लगा कर आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर और अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं गुस्साए छात्रों ने कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। हंगामा कर रहे आक्रोशित छात्रों को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी जिसमें दर्जन भर से अधिक छात्र के घायल होने की खबर है। बता दें कि पूसा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अखिल साहू अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहा थे।

इसी बीच एक अनियंत्रित पिकअप ने मोटरसाइकिल में ठोकर मार दी जिससे वो बाइक सहित एक पोल से टकरा गए। इस हादसे में छात्र को सिर में गंभीर चोट लग गई। घायल अवस्था में छात्र को इलाज के लिए विश्वविद्यालय के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से डाक्टरों ने उसे पूसा अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया।

डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया, छात्रों ने आरोप लगाया कि बिना ऑक्सीजन के ही हमें प्राइवेट गाड़ी से इलाज के लिए छात्र को मुजफ्फरपुर ले जाना पड़ा और रास्ते में ही जेल चौक के पास उसकी मौत हो गई। इसके बाद अपने साथी के मौत से गुस्साए छात्र काफी उग्र हो गए। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाह रही थी लेकिन छात्र मृतक के परिजनों के आने और वीसी को बुलाने की मांग पर अड़े थे। इसके बाद आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय के अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी और वहां खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया।

आक्रोशित छात्रों ने एकेडमिक बिल्डिंग में भी जमकर तोड़फोड़ की है। बाद में काफी संख्या में पहुंची पुलिस ने छात्रों की भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज शुरू कर दिया जिसमें दर्जन भर से अधिक छात्र के घायल होने की सूचना है। कुछ घायल छात्रों का इलाज सदर अस्पताल में भी चल रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है।

क्वाड बैठक में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन की मुलाकात पर रूस की नजर चीन में भी खलबली

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापानी दौरा इस लिहाज से काफी अहम है, क्यों कि रूस यूक्रेन जंग के दौरान तीन देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक मंच साझा करेंगे। इस दौरे में वह अमेरिका, जापान व आस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ अलग-अलग मुलाकात करेंगे। इन नेताओं की मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब यूक्रेन जंग के दौरान भारत और क्वाड देशों ('ैर्ह्ल एल्स्सू) के बीच मतभेद गहरे हुए थे। क्वाड की इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन भी सम्मलित हुए। कूटनीतिक लिहाज से क्वाड की यह बैठक बेहद उपयोगी है। भारत चीन सीमा विवाद को देखते हुए भारत के लिए क्वाड बेहद उपयोगी मंच है। आइए जानते हैं कि कूटनीतिक लिहाज से यह बैठक भारत के लिए कितनी उपयोगी है। इस बैठक पर रूस और चीन की पैनी नजर क्यों है। क्वाड का गठन क्यों हुआ। इसके गठन के पीछे क्या निहितार्थ हैं।

क्वाड शिखर सम्मेलन की यह बैठक क्यों है अहम ?

1- प्रो हर्ष वी पंत ने कहा कि जापान में हो रही क्वाड बैठक भारत के लिहाज से काफी अहम है। रूस और चीन की इस बैठक पर पैनी नजर होगी। उन्होंने कहा कि यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका व क्वाड देशों के संबंधों में थोड़ा खिंचाव देखने को मिला है। खासकर अमेरिका व आस्ट्रेलिया ने रूस के प्रति भारत की तटस्थता नीति की खुलकर निंदा की है। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन भी भाग ले रहे हैं। इस लिहाज से यह बैठक और उपयोगी हो जाती है।

2- इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। यह उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बैठक के बाद भारत और क्वाड देशों के संबंध एक बार फिर मधुर होने में मदद मिलेगी। खासकर अमेरिका और आस्ट्रेलिया से संबंध सामान्य होंगे। प्रो पंत ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग के दौरान क्वाड के प्रमुख देशों (अमेरिका, आस्ट्रेलिया और जापान) के राष्ट्राध्यक्षों के साथ पीएम मोदी एक मंच साझा करेंगे। तीनों देशों के बीच यूक्रेन जंग के दौरान रूस के साथ संबंधों को लेकर मतभेद उत्पन्न हुए थे। खासकर अमेरिका और आस्ट्रेलिया ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत का रूस के प्रति झुकाव का आरोप लगाया था।

3- हालांकि, भारत ने अपने स्टैंड को क्लीयर कर दिया था। भारत का कहना है कि वह किसी भी तरह के जंग के खिलाफ है। भारत का मत है दोनों देशों को वार्ता के जरिए अपने मतभेदों का समाधान करना चाहिए। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ हुए मतदान में भाग नहीं लेकर अमेरिका को और नाराज कर दिया था। भारत ने इस मामले में अपने दृष्टिकोण को साफ किया था। भारत ने साफ कर दिया था कि भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंध काफी मायने रखते हैं। इसलिए वह रूस के खिलाफ मतदान में भाग नहीं ले सकता है। भारत ने यह भी कहा था कि अमेरिका को भारत के हितों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए।

4- उन्होंने कहा कि भारत के सामरिक जरूरतों के लिए रूस जितना उपयोगी है, उतना ही चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका और क्वाड देशों का भी उसे साथ चाहिए। उन्होंने कहा भारत चीन सीमा विवाद को देखते हुए क्वाड भारत के लिए काफी अहम है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता भारत समेत दुनिया के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में क्वाड भारत के लिए काफी अहम है।

उन्होंने कहा कि इस बैठक में क्वाड नेताओं को हिंद-प्रशांत से जुड़े घटनाक्रम, साझा हितों से जुड़े समसामयिक वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान का अवसर मिलेगा। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन एवं आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। बता दें कि मार्च 2021 में डिजिटल माध्यम से हुई पहली बैठक के बाद क्वाड नेताओं के बीच यह चौथी वार्ता है। वाशिंगटन में सितंबर 2021 में क्वाड नेताओं ने उपस्थित होकर बैठक में हिस्सा लिया था, जबकि मार्च 2022 में डिजिटल माध्यम से बैठक हुई थी।

वाहन ईंधन पर उत्पाद शुल्क कटौती से केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी प्रभावित नहीं होगी - सीतारमण

नई दिल्ली (ईएमएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वाहन ईंधन पर उत्पाद शुल्क कटौती से केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी प्रभावित नहीं होगी। सीतारमण ने रविवार को कहा कि पेट्रोल में आठ रुपये और डीजल में छह रुपये की कटौती इन ईंधनों पर लगाए जाने वाले सड़क एवं अवसंरचना उपकर में की गई है जिसके संग्रह को राज्यों के साथ कभी साझा नहीं किया जाता। ऐसे में विपक्ष का यह आरोप सही नहीं है।

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और अन्य विपक्षी नेताओं ने कहा था कि सरकार ने शनिवार शाम को उत्पाद शुल्क में कटौती की जो घोषणा की है उससे केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी कम हो जाएगी। हालांकि, बाद में रविवार को चिदंबरम ने अपना बयान वापस लेते हुए कहा है कि करों में कटौती का भार अकेले केंद्र सरकार ही वहन करेगी।

निर्मला सीतारमण ने ट्विटर पर लिखा कि वह पेट्रोल और डीजल पर लगाए जाने वाले करों के बारे में उपयोगी जानकारी साझा कर रही हैं जो सभी के लिए लाभदायक होगी। उन्होंने कहा, ''मूल उत्पाद शुल्क, विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सड़क एवं अवसंरचना उपकर और कृषि एवं अवसंरचना विकास कर को मिलाकर पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क होता है। मूल उत्पाद शुल्क राज्यों के साथ साझा किया जाता है जबकि एसएईडी, आरआईसी और एआईडीसी को साझा नहीं किया जाता।''

वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोल पर आठ रुपये प्रति लीटर और डीजल पर छह रुपये प्रति लीटर की उत्पाद शुल्क कटौती पूरी तरह से आरआईसी में की गई है। नवंबर, 2021 में जब पेट्रोल पर पांच रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर घटाए गए थे तब भी कटौती आरआईसी में ही की गई थी।

केंद्र-राज्य कर साझेदारी की व्यवस्था के तहत केद्र जो कर संग्रह करता है उनमें से 41 प्रतिशत राज्यों के पास जाता है। हालांकि, इनमें उपकर के जरिए लेवी के रूप में जुटाया गया कर शामिल नहीं होता। पेट्रोल और डीजल पर लगाया जाने वाला ज्यादातर कर 'उपकर' होता है।

शनिवार की कटौती से पहले पेट्रोल पर केंद्रीय कर 27.90 रुपये प्रति लीटर था, मूल उत्पाद शुल्क सिर्फ 1.40 रुपये प्रति लीटर था। इसी तरह डीजल पर 21.80 रुपये का कुल केंद्रीय कर था और मूल उत्पाद शुल्क सिर्फ 1.80 रुपये था। प्रति लीटर पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 11 रुपये और डीजल पर आठ रुपये था। पेट्रोल पर एआईडीसी 2.50 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर चार रुपये प्रति लीटर था।

पेट्रोल पर 13 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क आरआईसी के रूप में लगाया गया था और डीजल पर आठ रुपये प्रति लीटर इस तरह का शुल्क लगाया गया था। शनिवार की उत्पाद शुल्क कटौती इसी में की गई है। पेट्रोल पर सिर्फ 1.40 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 1.80 रुपये प्रति लीटर का बीईडी संग्रह राज्यों के साथ साझा किया जाता है।

निर्मला सीतारमण ने कहा, ''मूल उत्पाद शुल्क जिसे राज्यों के साथ साझा किया जाता है उसे छुआ भी नहीं गया है। अतः कर में दो बार की गई कटौती (पहली कटौती नवंबर में और दूसरी शनिवार को) का भार केंद्र उठाएगा।''

अतीत में नष्ट किए गए सभी मंदिरों का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए - प्रमोद सांवत

पणजी (ईएमएस)। गोवा के सीएम प्रमोद सांवत ने कहा है कि अतीत में नष्ट किए गए सभी मंदिरों का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने राज्य में पुर्तगालियों द्वारा आक्रमण के समय नष्ट किए गए मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए बजटीय आवंटन किया है।

सावंत ने यह भी कहा कि गोवा सरकार राज्य में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है और लोगों को गोवा के मंदिरों में आने के लिए प्रेरित कर रही है। आरएसएस की साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक मीडिया सम्मेलन में भाग लेते हुए गोवा के सीएम सावंत ने ये बातें कहीं।

उन्होंने कहा कि पुर्तगाली शासन के 450 वर्षों में हिंदू संस्कृति का विनाश हुआ और कई लोगों का धर्मांतरण हुआ। राज्य के मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। हम इस सब का कायाकल्प करने जा रहे हैं। मेरा मानना है कि जहां भी मंदिर नष्ट हो गए हैं, उन्हें फिर से बनाया जाना चाहिए। सावंत ने आगे कहा कि उनकी सरकार गोवा में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त काम कर रही है।

सीएम सावंत ने कहा कि उनकी सरकार ठसांस्कृतिक पर्यटनठ पर जोर दे रही है। हर गांव में एक दो मंदिर होते हैं। हमें लोगों को समुद्र तट से मंदिर तक ले जाना है। इस दौरान यूनिफार्म सिविल कोड (यूसीसी) पर बोलते हुए सावंत ने कहा कि गोवा में पहले से ही यूनिफार्म सिविल कोड लागू है। इसे हर राज्य में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं गर्व से कहता हूं कि गोवा आजादी के बाद से यूनिफार्म सिविल कोड का पालन कर रहा है। मेरा मानना है कि अन्य सभी राज्यों को यूसीसी का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने गोवा यूसीसी पर अन्य मुख्यमंत्रियों से भी चर्चा की है।

वास्तविक नियंत्रण रेखापर भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस का संयुक्त सैन्य अभ्यास

नई दिल्ली (ईएमएस)। वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस कई संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। इससे दोनों बलों के बीच संयुक्तता और एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सुरक्षा बल युद्ध की तैयारियों को बढ़ाने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। हाल ही में भारतीय सेना और आईटीबीपी ने चीन के साथ उत्तराखंड सीमा पर सक्रियता बढ़ाने के लिए केंद्रीय क्षेत्र के कोडनेम 'आईबीईएक्स' में एक संयुक्त अभ्यास किया था।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि जिस समय चीन के साथ अप्रैल-मई 2020 में एलएसी पर विवाद हुआ था। उसके बाद उस समय बनाई गई सड़क निर्माण की योजना के मुताबिक, सड़क निर्माण पर काम हो रहा है और इसके लिए जरूरी अनुमति ले ली गई है। सूत्रों के मुताबिक, दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में दुरबुक-श्योक-डीबीओ सड़क के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि नुब्रा घाटी पश्चिमी तरफ है और इसमें एयरबेस भी है, जिस पर अब सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में संचालन सहित पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है।

जापान रवाना होने से पहले बोले पीएम मोदी संबंध को करेंगे और मजबूत

नई दिल्ली (ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान की यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की यात्रा से पहले कहा है कि क्वाड देशों के नेता हिंद-प्रशांत क्षेत्र में घट रहे घटनाक्रम और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन से क्वाड देशों के नेताओं को उठाए गए कदमों की प्रगति की समीक्षा करने का मौका मिलेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी होगी, इसमें हम अमेरिका के साथ बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। दरअसल, क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के लिए रवाना हो रहे हैं। पीएम मोदी की यह तीसरी जापान यात्रा होगी। जापान में पीएम मोदी क्वाड सम्मेलन में नेताओं से चर्चा के अलावा नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, सुरक्षा, तकनीक समेत कई मुद्दे शामिल रहेंगे। पीएम मोदी 23 और 24 मई को जापान में आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। क्वाड सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ-साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस से भी मुलाकात करेंगे। यात्रा से पहले पीएम मोदी के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि क्वाड सम्मेलन का उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को लेकर सकारात्मक और क्रिएटिव एजेंडे को लागू करने पर जोर देना है। सम्मेलन के दौरान इस बात पर भी फोकस किया जाएगा कि इस क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है। साथ ही भविष्य में कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। पीएम मोदी के हवाले से यह भी बताया गया है कि भारत-जापान के बीच विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ बातचीत को लेकर उत्साहित हूं।

पश्चिम बंगाल में तूफानी हवा के साथ तेज वर्षा में 4 लोगों की मौत, बाधित हुई मेट्रो सेवा

कोलकाता (ईएमएस)। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से में शनिवार शाम तेज रफ्तार हवा और बारिश के कारण चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि अनेक लोग घायल हुए हैं। तेज हवा के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिर गए, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मौसम कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि काल बैसाखी ने कोलकाता के अलावा उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हुगली और पुरबा बर्धमान जिलों में दस्तक दी है।

तूफान ने पिछले कुछ दिनों की भीषण गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन इससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिकारी ने बताया कि तेज हवा के कारण पूर्वी बर्धमान जिले में एक दीवार गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। वहीं नदिया जिले में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कोलकाता के रवींद्र सरोबर झील में नाव पलटने से दो लड़कों की मौत हो गई। आपदा प्रबंधन मंत्री जावेद अहमद खान ने बताया कि महानगर के विभिन्न हिस्सों में कई पेड़ गिरे जिससे यातायात बाधित हुआ।

बिहार में ट्रेनों के ठहराव को लेकर बड़ा प्रदर्शन, राजधानी समेत 40 के रूट बदले, 23 गाड़ियां रद

पटना : दानापुर मंडल के बड़हिया स्टेशन पर 10 ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर यात्री रविवार की सुबह 10:00 बजे ट्रैक पर जमा होकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करने लगे। ट्रैक जाम होने के कारण ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप रहा। दिल्ली-हावड़ा मेन लाइन पर परिचालन बाधित होने से कई ट्रेनें जहां-तहां के स्टेशनों पर फंसी रहीं। रेल प्रबंधन द्वारा यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए 40 ट्रेनों का परिचालन दूसरे रूट से किया गया। रेलवे ट्रैक जाम रहने के कारण 23 ट्रेनों का परिचालन रद करने का निर्णय लिया गया। हावड़ा राजधानी, भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एवं हावड़ा अमृतसर अकाल तख्त एक्सप्रेस को किउल से वाया गया डीडीयू डायवर्ट कर दिया गया। दोनों ट्रेनों से मोकामा, हथिदह स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों को किउल से ट्रेन पकड़ने को कहा गया। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए मंडल रेल प्रबंधक प्रभात कुमार के निर्देश पर पटना जंक्शन से इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए प्लेटफार्म संख्या पांच से विशेष नान स्टाप ट्रेन 17:10 बजे डीडीयू के लिए रवाना की गई। दोनों ट्रेनों के यात्री इसी ट्र

जन हितैषी

युद्ध का अंजाम

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और किसी को नहीं पता है कि यह युद्ध कब और कैसे खत्म होगा लेकिन यह करीब-करीब साफ है कि रूस अभी नहीं जीत रहा है। रूस अब तक यूक्रेन की सरकार को बदलने और कीव पर कब्जा करने में नाकाम रहा है और अब तो रूस यूक्रेन के पूर्वी भाग के कुछ इलाकों में सिमटकर रह गया है। इतना ही नहीं रूस को यूक्रेनी सेना को पीछे धकेलने में भी मुश्किलें आ रही हैं। तो क्या यूक्रेन युद्ध जीत रहा है? यूक्रेनी सेना ने बेहद चतुराई से काम किया है और रूसी सेना की कमजोरियों पर वार कर फायदा उठाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौलिक स्तर पर पुतिन पहले ही हार चुके हैं। जिस तरह से रूसी सेना ने यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया है उसे डॉक्यूमेंट किया गया है लेकिन यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को कितना नुकसान पहुंचाया है यह बेहतर तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है। यह सच है कि कई जगहों पर यूक्रेनी सेना पीछे हटी थी लेकिन अब उन जगहों पर फिर एक बार यूक्रेनी सेना का नियंत्रण है। इसमें पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा शामिल नहीं है क्योंकि वहां अभी भी रूसी सैनिक बड़े हिस्से में जमे हुए हैं। युद्ध में कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब किसी भी पक्ष की हार या जीत नहीं होती है। बराबरी पर छूट जाता है। ऐसे हालात में यह संभव है कि किसी पक्ष का अधिक नुकसान हुआ हो और किसी का कम लेकिन जीत या हार किसी की नहीं होती। विश्लेषकों का कहना है कि अगर यूक्रेन डोनबास में मौजूदा रूसी आक्रमण का सामना कर सकता है, तो यूक्रेनियन अगले कुछ हफ्तों में अपने जवाबी हमले को तेज कर देंगे। ऐसा लगता है कि रूस ने जो एज हासिल किया था उसे खो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि वह किस पॉइंट पर आगे बढना बंद कर देंगे और क्या यूक्रेनी सेना उन्हें पीछे धकेल सकेगी? नाटो देशों की ओर से यूक्रेन को दी जा रही आर्थिक और सामरिक सहायता से युद्ध अनिर्णय की दिशा में बढ़ता जा रहा है। किसी की जीत-हार होती नहीं दिख रही है। पर युद्ध जितना लंबा खिंचता जा रहा है, उसकी उतनी ही पीड़ा मानवता को भोगनी पड़ रही है। अभी तक का तथ्य तो यही है कि युद्धों ने दुनिया और सभ्यता को नुकसान तो बहुत पहुंचाया, परंतु कोई भी ताकतवर अपने से भिन्न मत या कमजोर शक्ति वाले को समाप्त कभी नहीं कर पाया। भारत के अतीत में देखें तो कृष्ण और जरासंध के बीच युद्ध हुआ, पर भगवान माने जाने वाले कृष्ण की जीत के बाद भी जरासंध के अनुयायी या मानने वाले अभी भी अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के बीच युद्ध हुए, मगर आज भी दोनों ही मतों को मानने वाले मौजूद हैं। शिया और सुन्नी संप्रदाय के बीच युद्ध हुए। लाखों लोग मारे गए। इसके बाद भी दोनों मत को मानने वालों की तादाद कम नहीं है। रंगभेद और नस्लभेद के नाम पर दुनिया में कई युद्ध और गृह युद्ध हुए। पर अंतिम निर्णय के दृष्टिकोण को स्वीकार करें तो इनका परिणाम शून्य है। इसके बावजूद दुनिया के सभ्य कहे जाने वाले मुल्क या समुदाय युद्ध क्यों करते हैं, यह खोज का विषय भी है और समझने का भी। एक विदेशी इतिहासकार ने दुनिया के इतिहास और युद्धों का अध्ययन कर बताया कि पिछले लगभग साढ़े तीन हजार वर्षों में दो सौ साठ साल ही ऐसे रहे हैं जिनमें कोई युद्ध नहीं हुए हैं। वरना दुनिया आपस में लड़ती रही है। रूस ने यूक्रेन पर युद्ध थोपा है। वह कितना क्रूर और भयावह है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भले ही संयुक्त राष्ट्र के नियम कहते हों कि आवासीय क्षेत्र या निहत्थे लोगों पर हथियार इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, पर रूस यूक्रेन को घुटने टेकने के लिए नागरिक क्षेत्रों पर लगातार बम बरसा रहा है। लगभग पचास लाख लोग यूक्रेन से पलायन कर गए हैं और शरणार्थी जीवन जी रहे हैं। निहत्थे नागरिक जिनका कोई हाथ न युद्ध के कराने में हैं, न जिनकी कोई युद्ध की आकांक्षा, वे सभी इस युद्ध का शिकार हो रहे हैं। हजारों बच्चे मारे गए हैं। युद्ध के नाम पर यह क्रूरता अभूतपूर्व है। तीन महीने हो चुके हैं जंग को चलते हुए, पर इसका अंत नजर नहीं आ रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह युद्ध दुनिया को नए सामरिक संतुलन व संगठन बनाने के लिए थोपा गया है। साथ ही एक और नए शीत युद्ध की शुरुआत भी इससे हो गई है।

भाजपा राहुल को धन्यवाद दे

राहुल गांधी ने लंदन जाकर भारत की राजनीति, सरकार, संघवाद, विदेश मंत्रालय आदि के बारे में जो बातें कहीं, वे नई नहीं हैं लेकिन सवाल यह है कि उन्हें विदेशों में जाकर क्या यह सब बोलना चाहिए? भारत में रहते हुए वे सरकार की निंदा करें, यह बात तो समझ में आती है, क्योंकि वे ऐसा न करें तो विपक्ष का धंधा ही बंद हो जाएगा। भारत का विपक्ष इतना टटपूंजिया हो गया है कि उसके पास निंदा के अलावा कोई धंधा ही नहीं बचा है। उसके पास न कोई विचारधारा है, न सिद्धांत है, न नीति है, न कार्यक्रम है, न जन-आंदोलन के कोई मुद्दे हैं। उसके पास कोई दिखावटी नेता भी नहीं हैं। जो नेता हैं, वे कालिदास और भवभूति के विदूषकों को भी मात करते हैं। उनकी बातें सुनकर लोग हंसने के अलावा क्या कर सकते हैं? जैसे राहुल गांधी का यह कहना कि भारत-चीन सीमा का विवाद रूस-यूक्रेन युद्ध का रूप भी ले सकता है। ऐसा मजाकिया बयान जो दे दे, उसे कुछ खुशामदी लोग फिर से कांग्रेस-जैसी महान पार्टी का अध्यक्ष बनवा देना चाहते हैं। जो व्यक्ति भारत की तुलना यूक्रेन से कर सकता है, आप अंदाज लगा सकते हैं कि उसके माता-पिता ने उसकी पढ़ाई-लिखाई पर कितना ध्यान दिया होगा? कोई जरुरी नहीं है कि हर नेता अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विशेषज्ञ हो लेकिन वह यदि अखबार भी ध्यान से पढ़ ले और उन्हें न पढ़ सके तो कम से कम टीवी देख लिया करे तो वह ऐसी बेसिर-पैर की बात कहने से बच सकता है। भारतीय राजनीति परिवारवाद और सत्ता के केंद्रीयकरण से ग्रस्त है, इसमें शक नहीं है लेकिन उसका विरोध करने की बजाय राहुल ने भारत को विभिन्न राज्यों का संघ बता दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? याने भारत एकात्म राष्ट्र नहीं है। ऐसा कहकर क्या अलगाववाद को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है? इसी तरह पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति की तुलना भारत से करने की तुक क्या है? भारत में कोई सरकार कभी अपनी फौज के इशारों पर नाची है? यह कहना बिल्कुल गलत है कि भारत के अखबारों और टीवी चैनलों पर भारत सरकार का 100 प्रतिशत कब्जा है। क्या आज भारत में आपात्काल (1975-77) जैसी स्थिति है? जो पत्रकार और अखबार मालिक खुशामदी हैं, वे अपने स्वार्थों की वजह से हैं। जो निष्पक्ष और निर्भीक हैं, उन्हें छूने की हिम्मत किसी की भी नहीं है। भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पर घमंडी होने का आरोप भी लगाया जाता रहा है लेकिन यही आरोप तो आज कांग्रेस के नेतृत्व को तबाही की तरफ ले जा रहा है। हमारे विदेश मंत्रालय के अफसरों पर आक्षेप करना भी उचित नहीं है। वे अत्यंत शिष्ट और उचित व्यवहार के लिए सारी दुनिया में जाने जाते हैं। कुछ भाजपा नेताओं ने राहुल के आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश भी की है। वह तो जरुरी था लेकिन उससे भी ज्यादा जरुरी यह है कि भाजपा अपने भाग्य को सराहे कि उसे राहुल-जैसा विरोधी नेता मिल गया है, जिससे उसको कभी कोई खतरा हो ही नहीं सकता। भाजपा को अगर कभी कोई खतरा हुआ तो वह खुद से ही होगा। भाजपा को चाहिए कि वह राहुल को धन्यवाद दे और उसकी पीठ थपथपाए। (लेखक-डॉ. वेदप्रताप वैदिक/ईएमएस)

दैनिक पंचांग

23 मई 2022 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

सोमवार 2022 वर्ष का 143 वां दिन
दिशाशूल पूर्व **ऋतु** ग्रीष्म।
विक्रम संवत् 2079 **शक संवत्** 1944
मास ज्येष्ठ (दक्षिण भारत में वैशाख)
पक्ष कृष्ण **पक्ष** शुक्ल
तिथि अष्टमी 11.35 बजे को समाप्त।
नक्षत्र शतभिषा 22.22 बजे को समाप्त।
योग वैधृति 01.05 बजे रात्र को समाप्त।
करण कौलव 11.35 बजे तदनन्तर तैतिल 23.06 बजे को समाप्त।

ग्रह स्थिति		लग्नारंभ समय	
सूर्य	वृष में	मिथुन	06.49 बजे से
चंद्र	कुंभ में	कर्क	09.03 बजे से
मंगल	मीन में	सिंह	11.19 बजे से
बुध	वृष में	कन्या	13.31 बजे से
गुरु	मीन में	तुला	15.42 बजे से
शुक्र	मीन में	वृश्चिक	17.56 ब.से
शनि	कुंभ में	धनु	20.12 बजे से
राहु	मेष में	मकर	22.18 बजे से
केतु	तुला में	कुंभ	00.04 बजे से
राहुकाल 7.30 से 9.00 बजे तक		मीन	01.37 बजे से
		मेष	03.07 बजे से
		वृष	04.47 बजे से

चन्द्रायु 22.2 घण्टे
रवि क्रान्ति उत्तर 20° 32'
सूर्य उत्तरायन
कलि अहर्गण 1871257
जूलियन दिन 2459722.5
कलियुग संवत् 5123
कल्पारंभ संवत् 1972949123
सृष्टि ग्रहारंभ संवत् 1955885123
वीरनिर्वाण संवत् 2548
हिजरी सन् 1443
महीना सव्वाल
तारीख 21

दिन का चौघड़िया			रात का चौघड़िया		
अमृत	05.53 से	07.22 बजे तक	चर	05.43 से	07.14 बजे तक
काल	07.22 से	08.50 बजे तक	रोग	07.14 से	08.45 बजे तक
शुभ	08.50 से	10.19 बजे तक	काल	08.45 से	10.17 बजे तक
रोग	10.19 से	11.48 बजे तक	लाभ	10.17 से	11.48 बजे तक
उद्वेग	11.48 से	01.17 बजे तक	उद्वेग	11.48 से	01.19 बजे तक
चर	01.17 से	02.45 बजे तक	शुभ	01.19 से	02.51 बजे तक
लाभ	02.45 से	04.14 बजे तक	अमृत	02.51 से	04.2 बजे तक
अमृत	04.14 से	05.43 बजे तक	चर	04.22 से	05.53 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। ■ Jagrutidaur.com, Bangalore

'तपती धरती' का जो ज़िम्मेदार, बचाव भी उसी से दरकार

मौसम विशेषज्ञों द्वारा ग्रीष्म ऋतू शुरू होने से पहले ही यह भविष्यवाणी कर दी गयी थी कि इस बार दुनिया के अधिकांश देश झुलसाने वाली अभूतपूर्व गर्मी का सामना कर सकते हैं। सहस्त्राब्दियों पुराने ग्लेशियर्स के लगातार पिघलते रहने के बीच जब यह ख़बर भी आयी थी कि पूरे विश्व को प्रकृतिक रूप से लगभग बीस प्रतिशत ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले अमेज़ॉन के सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र के जंगलों को ब्राज़ील सरकार के संरक्षण में विकास के नाम पर काट दिया गया है। तभी यह अंदाज़ा होने लगा था कि दुनिया भविष्य में अभूतपूर्व तपिश का सामना करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और पूरे विश्व विशेषकर भारत को भी इसबार झुलसती गर्मी का सामना करना पड़ा। देश के विभिन्न स्थानों पर 2 से लेकर 3 प्रतिशत तक सामान्य तापमान में वृद्धि दर्ज की गयी। राजधानी दिल्ली के मंगेशपुर नामक एक क्षेत्र में तो पारा 49 डिग्री सेल्सियस पार कर गया। जगह जगह सूखा पड़ने की ख़बरें आईं।

निश्चित रूप से आम लोग ग्लोबल वार्मिंग रुपी इस त्रासदी से पूरी तरह तो हरगिज़ नहीं निपट सकते। क्योंकि विकास और प्रगति के नाम पर छिड़ी विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा के ज़िम्मेदार दुनिया के शासक और सरकारें हैं। इन्हीं का काम ऐसी 'विकासवादी' योजनायें बनाना है जो प्रायः पर्यावरण विरोधी होती हैं। जिनमें हरे प्राकृतिक जंगल काटे जाते हैं और सीमेंट व कंक्रीट के 'तपते जंगलों' का विस्तार किया जाता है। परन्तु ऐसा भी नहीं है कि हम अपने,अपने घरों के आसपास का तापमान कम या स्थिर रखने के लिये अपने स्तर पर कुछ भी नहीं कर सकते। तपिश कम करने और ग्लोबल वार्मिंग से जूझने के ऐसे तमाम छोटे छोटे उपाय हैं जिनका सीधा संबंध सरकार या शासन से नहीं बल्कि आम लोगों से है। जिन्हें अपनाकर हम स्थानीय स्तर पर कम से अपने अपने घर परिवार में तो झुलसती गर्मी से राहत महसूस कर ही सकते हैं और प्रकृति प्रदत्त इस बेशक़ीमती जल और ऑक्सीजन युक्त धरा का सम्पूर्ण नहीं तो कुछ क़र्ज़ तो अदा कर ही सकते हैं।

सर्वप्रथम हमें अपनी यह सोच बनानी होगी और अपने बच्चों में भी पैदा करनी होगी कि वातावरण को कम से कम गर्म होने दें। इसके लिये 'धुंआ' ,अग्नि और गर्म हवा के उत्सर्जन को जितना संभव हो सके,कम करें। प्रायः देखा गया है कि लोग अपने घरों के बाहर कूड़ा करकट ख़ासकर प्लास्टिक पॉलीथिन आदि इकट्ठाकर उसमें आग लगा देते हैं। आज कल विशेषकर स्वछता अभियान के तहत जब घर घर से कूड़ा इकट्ठा करने का कार्य सरकारी स्तर पर किया जा रहा हो और इस व्यवस्था के बदले नक़द भुगतान भी जनता ही कर रही हो ऐसे में कूड़ा व प्लास्टिक आदि जलाने का ही कोई औचित्य नहीं है। कई बार यह भी देखा गया है कि स्वयं नगर परिषद / निगम के सफ़ाई कर्मचारी ही झाड़ू से एक जगह कूड़ा इकट्ठा कर उसमें आग लगा देते हैं। कबाड़ का काम करने वाले तमाम लोग रबड़ आदि जलाकर ज़हरीला काला धुआं पैदा करते हैं। इस पर भी नियंत्रण पाना ज़रूरी है। स्टेशन के आस पास बैठे भिखारी तो सर्दियों के अतिरिक्त गर्मी में भी कूड़ा जलाकर प्रदूषण फैलते हैं। गाय-भैंस पालक प्रायः मच्छर भगाने की परंपरा के नाम पर पशुओं के आस पास धुआं करते हैं जिससे पशु भी परेशान होते हैं और आस पास का पूरा क्षेत्र भी प्रदूषित होता है। परन्तु न तो स्वयं इनकी समझ में आता है कि यह इसी स्वर्ग रुपी पृथ्वी को कितना नुक़सान पहुंचा रहे हैं न ही इन्हें कोई समझने वाला है।

अपने आसपास के वातावरण को और अधिक गर्म होने से बचाने के लिये दूसरा उपाय है कम से कम विद्युत् खपत की जाये । विशेषकर गर्मियों में बेतहाशा व अनावश्यक रूप से चलने वाले एयर कंडीशनर्स, वातावरण को सबसे अधिक गर्म करते हैं। बड़े मकानों में तो कई कई ए सी लगाकर अधिक से अधिक बिजली बिल चुकाने व वातावरण को गर्म करने में साझीदार बनने से बेहतर है कि अपने घरों को सेंट्रली एयर कूल्ड करने की व्यवस्था करें। इससे कम बिजली ख़र्च में और पर्यावरण को हानि पहुंचाये बिना हम गर्मी में अपने मकानों को ठण्डा रख सकते हैं।सभी विद्युत् उपकरण ज़रूरी होने पर ही इस्तेमाल करें। आवश्यकता न हो तो बत्ती पंखे आदि बंद ही रखें। इन बातों को अपनी आदतों में शामिल करना होगा। इसके साथ साथ अपने घरों में अधिक से अधिक पौधे गमलों में लगायें। वृक्षारोपण को अपनी जीवनचर्या में शामिल करें। पार्कों में सड़कों के किनारे ,शमशान-क़ब्रिस्तान,धर्मस्थलों जहाँ भी जगह हो अधिक से अधिक वृक्ष लगायें। अपने मकान या ज़मीन पर बड़े फलदार व छायादार वृक्ष लगायें।

धरती पर बढ़ता जल संकट भी बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम है। जहाँ हम प्रदूषण नियंत्रित कर व वृक्षारोपण आदि के माध्यम से वातावरण को वर्षानुकूल बनाने में सहायक हो सकते हैं वहीं जल की बर्बादी रोककर भी हम धरती व पर्यावरण के साथ साथ अपनी अगली नस्लों को भी अनुकूल वातावरण देने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप सड़कों गलियों में चलें तो अक्सर टूंटियों से पानी बहता रहता है। जहाँ पानी बहता दिखाई दे उसे तुरंत बंद करें। यदि किसी जगह टूंटी ख़राब है तो सरकारी कर्मचारी की प्रतीक्षा करने के बजाय पास पड़ोस के लोग स्वयं टूंटी का प्रबंध कर जल की बर्बादी को रोकें। तमाम लोग अपने घरों के सामने की सड़कों पर और अपने मकानों की फ़र्श आदि धोने में बेतहाशा पानी बर्बाद करते हैं। रोज़ाना कारें धोते हैं। यह सब अनावश्यक है। हर काम सीमा के भीतर होना चाहिये। और हर एक को यह महसूस करना चाहिये कि जिस जल को वह बहा रहा है वह स्वयं उसके,उसके बच्चों व मानव जीवन के लिये कितना अनिवार्य व उपयोगी है। आज पृथ्वी पर भीषण गर्मी व जल संकट के रूप में जो भी नज़र आ रहा है ज़ाहिर है हम ही उसके ज़िम्मेदार भी हैं। और इस 'तपती धरती' व जलसंकट का जो भी ज़िम्मेदार है बचाव के उपाय भी निश्चित तौर पर उसी से दरकार होंगे। (लेखिका-- निर्मल रानी/ ईएमएस)

क्या होगा देश का....? एक मिट्टी का तेल छिड़क रहा.... दूसरा चिंगारी ढूँढ रहा....!

(धर्म पर हावी सियासत)

आजादी के बाद शायद पहली बार आज भारत एक अजीब दौर से गुजरने को मजबूर है, जहां एक सियासी दल कथित तौर पर देश में मिट्टी का तेल छिड़क रहा है, तो दूसरा दल चिंगारी खोज रहा है, आखिर ऐसी स्थिति में इस देश का भविष्य क्या होगा? यह अहम चिंता आज देश के ''कर्णधारों'' को नहीं बल्कि आम देशवासी की है, जो अपने जीवन यापन सहित कई अन्य समस्याओं से जूझ रहा है, आज की सियासत जहां धर्म का सहारा लेकर अगले पच्चीस साल तक सत्ता में बने रहने का सुनहरा ख्वाब देख रही है, वहीं इसी घिनौनी सियासत के कुछ स्वार्थी शोले पूरे देश को साम्प्रदायिकता के दावानल में पूरे देश को झौंकने की कोशिश कर रहे हैं आखिर इस देश का ऐसे में भविष्य क्या होगा?

आज देश में धर्मान्धता इतनी अधिक हावी हो गई है कि अब देश के हर मंदिर-मस्जिद को शक की नजर से देखा जाने लगा है और हर सियासी नेता मंदिर-मस्जिद में जाकर ''पुरातत्व शास्त्री'' बनने की कोशिश कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहा है। उसे हर मंदिर- मस्जिद में छद्म धर्म नजर आने लगा है, जिसके सहारे वह अपनी सियासी स्वार्थ सिद्धी करना चाहता है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दो दशक पहले अयोध्या-बाबरी मस्जिद के चलते भी सियासत इतनी हावी नहीं हो पाई थी, जितनी की आज ज्ञानवापी के मुद्दें पर हावी हो रही है, अभी तो आगे मथुरा तथा अन्य आराध्य स्थालों पर भी सियासी नजर है, यही नहीं यह सिलसिला कहां जाकर थमेगा? इसका उत्तर भी किसी के भी पास नहीं है, क्योंकि अभी तो यह सिलसिला उत्तरप्रदेश में ही पूरा नहीं हो पा रहा है, मध्यप्रदेश व अन्य प्रदेशों के धार्मिक स्थलों की बारी कब आएगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जबकि आज से इक्कत्तीस साल पहले 1991 में संसद द्वारा पारित ''पूजा कानून'' ने सिर्फ अयोध्या प्रसंग को ही इस कानून की बाध्यता से छूट दी थी बाकी तो किसी भी विवाद को इस कानून के दायरे से बाहर नहीं रखा था, जिससे ज्ञानवापी, मथुरा आदि सभी शामिल है, किंतु उस कानून को लागू करके उसके तहत् कार्यवाही करने वाली सरकार ही कुछ नहीं कर उसमें अपनी सियासत देख रही हो तो, इसे क्या कहा जाए? फिर देश का रक्षक कौन?

आज इक्कत्तीस साल पहले (1991) में संसद ने जो कानून पारित किया था, उसमें कहा गया था कि देश के स्वतंत्रता दिवस अर्थात् पन्द्रह अगस्त 1947 के बाद देश की किसी भी धार्मिक पुरातात्विक धरोहर के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, न ही उसे विवाद का मुद्दा ही बनाया जाएगा और यदि किसी ने इस दिशा में कोई प्रयास किया तो उसे उक्त कानून के तहत दण्डित किया जाएगा, अब यह तो सही है कि उस कानून की ज्ञानवापी की आड़ में धज्जियां तो उड़ाई जा रही है, किंतु ऐसे दोषियों को दण्डित कौन करें? जब दण्ड देने वाला ही इस अपराध के दोषियों में शामिल हो? इसीलिए इस मसले पर पूरा देश चिंतित और परेशान है। ....और यह भी सही है कि अभी इस सिलसिले को नहीं रोका गया तो यह सिलसिला कहाँ-कहाँ तक पहुंचेगा, इसकी फिलहाल कल्पना भी मुश्किल है? शायद देश का कोई भी प्रमुख सियासी या धार्मिक शहर इससे वंचित नहीं रह पाएगा? फिर क्या होगा? क्या इसी माहौल के साये में हम हमारी आजादी की ''पचहत्तरवीं'' (हीरक) जयंती मनाएगें?

इसके साथ ही सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि इस सियासी व मजहबी छूत के रोग को रोकने का अब तक किसी ने भी प्रयास नहीं किया, उल्टे इसके विस्तारण की दिशा में ही प्रयास किये गये है? जबकि देश पर शासनारूढ़ राजनीतिक दल व उसके सियासतदारों को यह करना चाहिये? ऐसे माहौल को लेकर यदि कोई एकमात्र सर्वाधिक चिंतित वर्ग है तो वह देश का आम नागरिक है, जिसे अपने साथ देश की भी चिंता है।

अब यही हर किसी की समझ से बाहर है कि मिट्टी का तेल छिड़के इस देश को चिंगारी से कैसे बचाया जाए? और यह पुनीत कार्य करे कौन? (लेखक- ओमप्रकाश मेहता/ ईएमएस)

आज का इतिहास 23 मई

1568 नीदरलैंड में विद्रोह भड़का.
1853 अर्जेन्टीना में नया संविधान प्रभावी हुआ.
1911 रूस ने तुर्की को मोटे नीग्रो सीमा से फौजें हटाने को कहा.
1920 इंडोनेशिया में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ.
1926 फ्रांस ने लेबनान को गणराज्य घोषित किया.
1948 बचेन्द्री पाल एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही बनी.
1949 जर्मनी संघीय गणराज्य अस्तित्व में आया.
1969 मलेशिया के दंगों में मरनेवालों की संख्या पांच सौ से अधिक पहुंच गयी.
1971 पूर्वी तुर्की में भूकंप से एक हजार से अधिक लोग मारे गए.
1977 नीदरलैंड से मदद के लिए वहाँ के एक स्कूल में 161 लोगों को बंधक बनाने के अलावा एक रेलगाड़ी का अपहरण कर लिया.
1988 हंगरी को कम्युनिस्ट पार्टी ने राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की घोषणा की.
1992 अमरीका और सोवियत संघ से अलग हुए चार गणराज्यों के बीच प्रक्षेपास्त्र कटौती पर हस्ताक्षर किए.
1994 उत्तरी यमन ने दक्षिणी के महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जे के लिए स्कैड प्रक्षेपास्त्र से हमले किए.
1995 इजरायल के पूर्वी यरूशलम में अरब जमीन पर कब्जा करने की योजना रद्द कर दी.

भीषण गर्मी, पिघलते ग्लेशियर, बाढ़ और सूखा, हमारी पीढ़िया भुगतेंगी खामियाजाः रिपोर्ट

- मानव गतिविधियों के कारण धरती, महासागर व वातावरण में आ रहा है व्यापक बदलाव

न्यूयार्क (ईएमएस)। पूर्वी अफ्रीका में सूखे के कारण इमरजेंसी जैसे हालात दक्षिण में बाढ़ जबकि भारत और पाकिस्तान में भीषण गर्मी पड़ रही है। पिछले सात वर्षों ने अब तक के सर्वाधिक गर्म साल होने का रिकॉर्ड बनाया है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2021 रिपोर्ट जारी की है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की यह रिपोर्ट ऐसे समय में प्रकाशित हुई है जब मौसम में होने वाले गंभीर बदलावों से हाल के दिनों में करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2021 के दौरान, जलवायु परिवर्तन के चार प्रमुख संकेतकों, ग्रीनहाउस गैस की सघनता, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, महासागर का बढ़ता तापमान और समुद्री अम्लीकरण ने नया रिकॉर्ड बनाया है। ?रिपोर्ट के अनुसार यह दिखाता है कि मानव गतिविधियों के कारण धरती, महासागर व वातावरण में व्यापक बदलाव आ रहा है। इससे विकास व पारिस्थितिकी तंत्रों पर लंबे समय में दुष्परिणाम होंगे। यूएन मौसम विज्ञान एजेंसी के महासचिव पेटेरी टालस ने कहा कि कुछ ही समय में एक और सर्वाधिक गर्म साल देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी जलवायु हमारी आंखों के सामने बदल रही है। मानव-जनित ग्रीनहाउस गैस में एकत्र ताप के कारण, धरती आने वाली कई पीढ़ियों तक गर्म होता रहेगी। टालस ने कहा कि कुछ ग्लेशियर में पिघलाव इतना भीषण है कि उसे उलट पाना सम्भव नहीं है। इसके जिसके दीर्घकालीन दुष्परिणाम होने की आशंका है। उन्होंने सचेत किया कि इस संकट को टालने के लिये वातावरण में एकत्र कार्बन को हटाना होगा।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री (सेल्सियस) तक सीमित करने के लिए, हमें अक्षय ऊर्जा में तेजी लाने और ऊर्जा उत्पादन को बदलने की जरूरत है। कई देशों में, सौर और पवन पहले से ही ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र जीवाश्म ईंधन क्षेत्र की तुलना में तीन गुना अधिक रोजगार पैदा करता है। वही यूएन महासचिव के क्लाइमेट एक्शन एडवाइजर सेल्विन हार्ट ने कहा है कि सभी प्रमुख क्लाइमेट इंडिकेटर स्पष्ट रूप से गलत दिशा में जा रहे हैं। बहुत अधिक महत्वाकांक्षा और तात्कालिकता के बिना, हम 1.5 डिग्री लक्ष्य को बनाए रखने मौका खोने वाले हैं। पिछले वर्ष के आरम्भ और अन्त में ला नीना के असर के कारण, 2021 सात सबसे गर्म सालों में से केवल एक ही साबित हुआ। ला नीना की वजह से अधिक ठंड भी देखने को मिली। मगर बढ़ते तापमान के रुझान में बदलाव नहीं आया है। बदलती जलवायु का सीधा असर रोजमर्रा के जीवन में मौसम की घटनाओं में देखने को मिलता है। इनकी वजह से सैकड़ों अरब डॉलर का नुक़सान हुआ है। इसके साथ हीमानव जीवन व कल्याण को भी भीषण क्षति पहुंची है। 2021 में औसत वैश्विक तापमान में पूर्व-औद्योगिक काल की तुलना में लगभग 1.11ओए अधिक देखा गया।

(नई दिल्ली) दलित वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी ने तैयार किया यूपी वाला फार्मूला

नई दिल्ली (ईएमएस)। जैसे जैसे गुजरात विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने अभियान को तेज कर रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा ने भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा अपनी दलित पहुंच को तेज करना चाहती है। इसी कड़ी में भाजपा ने दलित वोट बैंक को देखते हुए खुद को उनकी पार्टी के रूप में पेश करने की कोशिश शुरू की है। इन्हें अब तक परंपरागत रूप से बसपा का वोट बैंक माना जाता है। जैसे जैसे गुजरात विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने अभियान को तेज कर रही हैं। इसी

शब्द पहेली - 7294

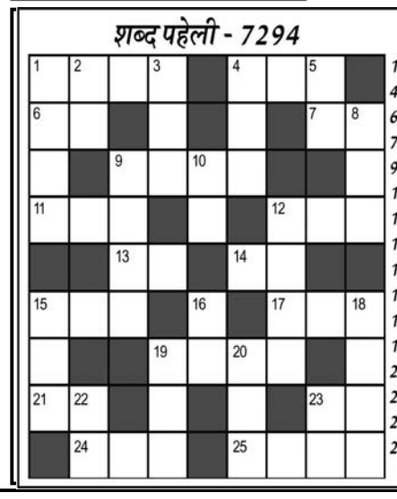

बाएँ से दाएँ

1. कलाकार, अदाकार-4
4. फूलों की छोटी माला, वेणी-3
6. पैर, पांव-2
7. अधिकार-2
9. खानाबदोश, बंजारा-4
11. राशन, खाद्य सामग्री-3
12. टेसू के फूल-3
13. कपोल, रुखसार-2
14. विजय-2
15. डोली उठाने वाले-3
17. जल प्रपात-3
18. गठबंधन-4
21. पानी, जल-2
23. नौका-2
24. देह, काया, शरीर-3
25. अगुवा, राह दिखाने वाला-4

ऊपर से नीचे

1. उपवास का खाना-4
2. झुका हुआ-2
3. व्यवहार-3
4. समयघोष-3
5. मार्ग, पथ-2
8. गागर, घड़ा, घट-3
9. स्मारक-4
10. हत्या, कत्ल-2
12. पत्तों के गिरने का मौसम-4
15. कथा, गाथा-3
16. अष्टम-2
18. नामचीन-4
19. रवाना होना-3
20. विदूषक, मसखरा-3
22. ईश्वर, भगवान-2
23. बटन, स्विच-2

शब्द पहेली -7293 का हल

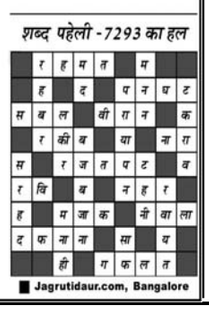

■ Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाचार

बीसीसीआई ने घोषित की भारतीय टीम , दक्षिण अफ्रीका सीरीज में राहुल , इंग्लैंड सीरीज में रोहित होंगे कप्तान

मुम्बई (ईएमएस)। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड दौरे के लिए टीम घोषित कर दी है। भारतीय टीम को इंग्लैंड से एक टेस्ट खेलना है जबकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उसे पांच टी-20 मैचों की सीरीज खेलने है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए लोकेश राहुल को कप्तान बनाया गया है जबकि टीम में दिनेश कार्तिक के अलावा अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, आवेश खान और रवि बिश्नोई जैसे खिलाड़ियों को भी शामिल किया है। उमरान ने आईपीएल में अपनी तेज गेंदबाजी के कारण सबका ध्यान खींचा है। इसके अलावा आवेश ने भी अच्छी गेंदबाजी की जबकि कार्तिक ने अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया।

वहीं इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे। अनुभवी चेतेश्वर पुजारा को टीम में शामिल किया गया है। पुजारा ने हाल में काउंटी क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया था। इसके अलावा हनुमा विहारी और शुभमन गिल को भी टीम में जगह दी गयी है जबकि विकेटकीपिंग के तौर पर ऋषभ पंत के साथ ही केएस भारत को भी शामिल किया गया है। जडेजा, अश्विन, शार्दुल ठाकुर को भी टीम में रखा है। वहीं अनुभवी शिखर धवन को आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भी टीम में जगह नहीं मिली है। उनकी जगह युवा बल्लेबाज दीपक हुड्डा और रुतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है।

टेस्ट टीम : रोहित शर्मा (कप्तान), लोकेश राहुल (उपकप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी,

वैश्विक कारकों और विदेशी संस्थागत निवेशकों के रुझानों से तय होगी बाजार की दिशा

- मासिक डेरिवेटिव निपटान की वजह से भी घरेलू बाजारों में देखा जा सकता है उतार-चढ़ाव

नई दिल्ली (ईएमएस)। इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों की दिशा वैश्विक कारकों और विदेशी संस्थागत निवेशकों के रुझानों से तय होगी। इसके अलावा मासिक डेरिवेटिव निपटान की वजह से घरेलू बाजारों में उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है। बाजार के जानकारों का कहना है ?कि पिछले कुछ सत्रों में स्थानीय बाजारों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि, निफ्टी में पांच सप्ताह की गिरावट के सिलसिले के बाद तीन फीसद की अच्छी साप्ताहिक बढ़त देखने को मिली है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और सुस्ती दुनियाभर के बाजारों के लिए प्रमुख चिंता का विषय है। इस वजह से विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बिकवाली कर रहे हैं। हालांकि, घरेलू निवेशकों के समर्थन के कारण भारतीय बाजार बेहतर स्थिति में हैं। वैश्विक मोर्चे पर फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक का ब्योरा 25 मई को जारी किया जाएगा, जो बाजार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा डॉलर सूचकांक का रुख और जिंसों के दाम भी बाजार को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

बाजार ?विशेषज्ञों का कहना है ?कि पिछले सप्ताह बाजार में उतार-चढ़ाव रहा। वृहद आर्थिक आंकड़ों, मौजूदा तिमाही नतीजों के सीजन और डेरिवेटिव निपटान की वजह से यह सिलसिला इस सप्ताह भी जारी रह सकता है। एफओएमसी की बैठक का ब्योरा, अमेरिका के जीडीपी के अनुमान और बेरोजगारी के आंकड़े वैश्विक बाजारों की धारणा को प्रभावित करेंगे। कुल मिलाकर हमारा मानना है कि इस सप्ताह भी बाजारों में उतार-चढ़ाव रहेगा। वृहद स्तर पर कई चीजें मसलन ऊंची मुद्रास्फीति और आक्रामक तरीके से ब्याज दरों में बढ़ोतरी बाजार को प्रभावित करेगी। इस सप्ताह के दौरान सेल, जोमैटो, अडाणी पोर्ट्स, दीपक फर्टिलाइजर्स, इंटरग्लोब एविएशन, हिंडाल्को, एनएमडीसी, गेल और गोदरेज इंडस्ट्रीज के तिमाही नतीजे आएंगे। उनका कहना है ?कि आगे चलकर वैश्विक रुख तिमाही नतीजों का अंतिम चरण और रूस-यूक्रेन युद्ध बाजार की दिशा को प्रभावित करेगा।

म्यूचुअल फंड कंपनियों ने 2021-22 में एनएफओ से 1.08 लाख करोड़ जुटाए

नई दिल्ली (ईएमएस)। शेयर बाजारों में तेजी और खुदरा निवेशकों की रुचि बढ़ने के बीच परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां (एएमसी) 2021-22 में 176 नई कोष पेशकश (एनएफओ) लेकर आई हैं, जिनके जरिये कुल 1.08 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए। नकदी की सख्त स्थिति, ब्याज दरों में बढ़ोतरी, शेयर बाजार में मजबूती, दफ्तर से काम फिर शुरू होने के बाद आगे चलकर एनएफओ में रुचि घट सकती है। वहीं निश्चित परिपक्वता वाली योजनाओं (एफएमपी) में उल्लेखनीय रूप से नई पेशकशें देखने को मिल सकती हैं। उन्होंने कहा कि लगभग सभी एएमसी ने विभिन्न श्रेणियों में नई योजनाएं पेश की हैं और पहले मौजूद उत्पादों के अंतराल को पाटने का काम किया है। उन्होंने बताया कि निवेश के उद्देश्यों में अंतर, विशिष्ट योजनाओं में निवेशकों की रुचि, धन की उपलब्धता, कोष प्रबंधकों की विश्वसनीयता और शेयर बाजारों के प्रदर्शन के आधार पर नई पेशकशों की संख्या तय होगी। आ?धिका?रिक आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में 176 नई कोष पेशकशें आईं। इन एनएफओ के जरिये 1,07,896 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कहीं ऊंचा आंकड़ा है। 2020-21 में 84 एनएफओ आए थे और इनके जरिये कुल 42,038 करोड़ रुपए जुटाए गए थे।

बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 425 परियोजनाओं की लागत 4.83 लाख करोड़ बढ़ी

- मार्च-2022 तक इन परियोजनाओं पर खर्च हो चुके हैं 13,88,760.73 करोड़

नई दिल्ली (ईएमएस)। देरी और अन्य कारणों की वजह से बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 150 करोड़ रुपये या इससे अधिक के खर्च वाली 425 परियोजनाओं की लागत में तय अनुमान से 4.83 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 150 करोड़ रुपये या इससे अधिक की लागत वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी करता है। मंत्रालय की मार्च-2022 की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की 1,579 परियोजनाओं में से 425 की लागत बढ़ी है, जबकि 664 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन 1,579 परियोजनाओं के क्रियान्वयन की मूल लागत 21,95,196.72 करोड़ रुपये थी, जिसके बढ़कर 26,78,365.62 करोड़ रुपये पर पहुंचने का अनुमान है। इससे पता चलता है कि इन परियोजनाओं की लागत 22.01 प्रतिशत या 4,83,168.90 करोड़ रुपये बढ़ी है। मार्च-2022 तक इन परियोजनाओं पर 13,88,760.73 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, जो कुल अनुमानित लागत का 51.85 प्रतिशत है। हालांकि, मंत्रालय का कहना है कि यदि परियोजनाओं के पूरा होने की हालिया समयसीमा के हिसाब से देखें, तो देरी से चल रही परियोजनाओं की संख्या कम होकर 561 पर आ जाएगी। रिपोर्ट में 606 परियोजनाओं के चालू होने के साल के बारे में जानकारी नहीं दी गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है ?कि 664 परियोजनाओं में 94 परियोजनाएं एक महीने से 12 महीने, 124 परियोजनाएं 13 से 24 महीने की, 331 परियोजनाएं 25 से 60 महीने की और 115 परियोजनाएं 61 महीने या अधिक की देरी में चल रही हैं। इन 664 परियोजनाओं की देरी का औसत 42.41 महीने है। इन परियोजनाओं की देरी के कारणों में भूमि अधिग्रहण में विलंब, पर्यावरण और वन विभाग की मंजूरियां मिलने में देरी और बुनियादी संरचना की कमी प्रमुख है। इनके अलावा परियोजना का वित्तपोषण, विस्तृत अभियांत्रिकी को मूर्त रूप दिये जाने में विलंब, परियोजना की संभावनाओं में बदलाव, निविदा प्रक्रिया में देरी, ठेके देने व उपकरण मंगाने में देरी, कानूनी व अन्य दिक्कतें, अप्रत्याशित भू-परिवर्तन आदि की वजह से भी इन परियोजनाओं में विलंब हुआ है।

चीन छोड़कर भारत आ सकता है ऐप्पल

- निर्माण और व्यापार की संभावनाओं पर कर रहा विचार

नई दिल्ली (ईएमएस)। कोरोना काल के बाद जहां दुनियाभर के बाजार में कोहराम मचा हुआ है, ऐसे में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी का नतीजा है कि तमाम वैश्विक दिग्गजों कंपनियों की नजर में भारत निवेश के लिए सुरक्षित बाजार बन रहा है। कई बड़ी कंपनियां अन्य देशों से अपना कारोबार समेट कर भारत में पैठ जमाने की कोशिश में लगी हैं। ताजा मामला टेक जगत की दिग्गज कंपनी ऐप्पल से जुड़ा है। जानकारी मिली है कि ऐप्पल चीन से अपने उत्पादन को दूसरे देश में ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है और उसे भारत एक अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है। एप्पल ने अपने कई अनुबंध निर्माताओं को निर्देश दिया है कि वह चीन के बाहर उत्पादन बढ़ाना चाहता है। भारत और वियतनाम में फिलहाल ऐप्पल के वैश्विक उत्पादन की बहुत ही कम हिस्सेदारी है। अनुमानों के अनुसार, स्वतंत्र निर्माता चीन में 90 प्रतिशत से अधिक ऐप्पल उत्पादों जैसे आईफोन, आईपैड और मैकबुक कंप्यूटरों का निर्माण करते हैं। पिछले महीने ऐप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा था कि उनकी आपूर्ति श्रृंखला वास्तव में वैश्विक है, और इसलिए उत्पाद हर जगह बनाए जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे अन्य देशों में संभावनाओं पर लगातार विचार कर रहे हैं।

जानकार बताते हैं कि पिछले कुछ समय में ऐप्पल के वरिष्ठ अधिकारी लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। चीन से अपना कारोबार समेटने के पीछे एक्सपर्ट बीजिंग के दमनकारी शासन और अमेरिका के साथ उसके बढ़ते विवाद को वजह बता रहे हैं। पर्यवेक्षकों के अनुसार, चीन पर ऐप्पल की निर्भरता एक बड़े जोखिम से भरी है। एप्पल की निर्माण योजनाओं से परिचित लोगों के अनुसार, कंपनी अपनी बड़ी आबादी और कम लागत के कारण भारत को अगले चीन के रूप में देखती है। दरअसल, चीन में कुशल श्रमिकों की तादाद इतनी है कि यह संख्या कई एशियाई देशों की आबादी से अधिक है। इसके अलावा एप्पल ने चीन में स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर काम किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके ठेकेदारों के पास बड़े पैमाने पर प्लांट में आईफोन तैयार करने, उन्हें स्टोर करने और उनकी सप्लाई के लिए पर्याप्त मात्रा में आधारभूत ढांचा, आपूर्ति ढांचा और श्रमिक हों।

वर्ष 2020 की शुरुआत में कोविड महामारी के दुनिया भर में फैलने से पहले ही ऐप्पल चीन से दूर होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महामारी ने उसकी प्लानिंग को रोक दिया। एप्पल फिर से दबाव बना रहा है और ठेकेदारों को निर्देश दे रहा है कि वे नई विनिर्माण क्षमता की तलाश करें। 2021 में बिजली की कटौती ने चीन की निर्भरता को और खराब कर दिया। कोविड महामारी के चलते कई चीन ने अपने यहां कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इन प्रतिबंधों के कारण ऐप्पल ने पिछले दो वर्षों में केवल कुछ अधिकारियों और इंजीनियरों को ही चीन भेजा है, जिससे व्यक्तिगत रूप से उत्पादन स्थानों का निरीक्षण करना मुश्किल हो गया है।

आरबीआई का फरमान, बिना कार्ड के पैसा निकलने की सुविधा सभी बैंक जल्द दे

अभी कुछ बैंक कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा दे रहे

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश के अंदर बैंकिंग सेवाओं को आसान बनाने के लिए रिजर्व बैंक लगातार कदम उठा रहा है। ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देने की इसी कड़ी में अब सभी बैंकों के एटीएम से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के बिना ही पैसे निकालने की सुविधा शुरू होगी। अब वहां दिन दूर नहीं जब एटीएम से पैसे निकालने के लिए साथ में कार्ड रखने की जरूरत ही खत्म होगी। साथ ही क्लोनिंग के जरिए डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड को भी रोका जा सकेगा। हालांकि, अभी कुछ बैंक कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन ग्राहक सिर्फ अपने बैंक के एटीएम से ही ऐसा कर सकते हैं। दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालने पर यह सुविधा नहीं मिलती है। साथ ही सभी बैंकों के एटीएम में यह सुविधा नहीं है, मगर अब ऐसा जल्दी हो होगा।

रिजर्व बैंक ने 19 मई, 2022 को सर्कुलर जारी कर सभी बैंकों से यह सुविधा जल्द शुरू करने को कहा है। आरबीआई ने सर्कुलर में कहा है कि सभी बैंक, एटीएम नेटवर्क और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स अपने एटीएम पर इंट्रॉपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल (आईसीसीडब्ल्यू) की सुविधा उपलब्ध कराएं। साथ ही, एनपीसीआई को सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्क के साथ यूनिफाइनड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के इंटीग्रेशन की सलाह दी है। बिना कार्ड नगद निकासी की प्रक्रिया में यूपीआई का इस्तेमाल ग्राहकों की पहचान प्रमाणित (कस्टमर ऑथराइजेशन) करने के लिए किया जाएगा जबकि सेटलमेंट नेशनल फाइनेंशियल स्वीच/एटीएम नेटवर्क के द्वारा होगा।

रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस तरह के ट्रांजैक्शन पर अलग से कोई शुल्क नहीं लगेगा। पहले से निर्धारित इंटरचेंज फीस और कस्टमर फीस के अलावा कोई अन्य शुल्क नहीं लगेगा। साथ ही कार्डलेस ट्रांजेक्शन में पैसे निकालने की सीमा नियमित एटीएम विड्रॉल की तरह ही होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अभी कार्ड से जितना नगद निकालने की सीमा है, कार्डलेस ट्रांजेक्शन में भी वहीं सीमा रहेगी। ट्रांजेक्शन फेल होने पर मुआवजे का नियम पहले की तरह ही लागू रहेगा। अभी ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से मुफ्त में 5 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जबकि दूसरे बैंकों के एटीएम से मेट्रो शहरों में मुफ्त में 3 ट्रांजैक्शन और गैर-मेट्रो शहरों में 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मुफ्त सीमा के बाद ट्रांजेक्शन करने पर बैंक 21 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन फीस वसूलते हैं। कार्डलेस ट्रांजैक्शन में भी यही नियम लागू रहेगा।

पुतिन द्वारा यूक्रेन की स्वतंत्रता को अनदेखा करने और हमले के पर छात्रा ने उठाए सवाल, तिलमिलाई क्रेमलिन प्रवक्ता

मॉस्को (ईएमएस)। यूक्रेन पर हमलावर रूस हर हालत में युद्ध को सही बता रहा है और दूसरे देशों के हस्तक्षेप के अनुचित बता रहा है। ऐसा ही एक नजारा रूस के येकेतेरिनबर्ग शहर स्थित यूराल फेडरल यूनिवर्सिटी में वार्ता के दौरान दिखा जब एक छात्रा ने रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा के सामने व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन की स्वतंत्रता की अनदेखा करने और फरवरी में उस पर आक्रमण करने के फैसले पर सवाल उठाए। छात्रा के सवालों को सुनकर जखारोवा भड़क गईं। ब्रिटिश अखबार के मुताबिक छात्रा ने जखारोवा से पूछा कि रूसी सरकार और विदेश मंत्रालय दशकों से देश की संप्रभुता और राष्ट्रों की स्वतंत्रता के अधिकारों को लेकर गर्व से बात करता है, लेकिन पुतिन ने अचानक यूक्रेन की स्वतंत्रता और उसकी संप्रभुता को नजरअंदाज करने का फैसला कर लिया। इस पर जखारोवा छात्रा को रोका और कहा कि हमने यूक्रेन की संप्रभुता की कभी अनदेखी नहीं की है। क्रेमलिन की प्रवक्ता ने कहा कि हम उन कुछ देशों में से एक हैं, जिन्होंने देशों की स्वतंत्रता और संप्रभुता को केवल कागज पर ही नहीं, बल्कि वास्तव में भी माना है।

इसके बाद छात्रा ने क्रीमिया के विलय को लेकर आयोजित किए गए 'जनमत संग्रह' की वैधता पर भी सवाल उठाया और उसे अवैध बताया। इस पर प्रवक्ता भड़क उठीं और कहा कि आप जनमत संग्रह को अवैध क्यों मानते हैं? इस पर छात्रा ने जवाब दिया कि क्योंकि संग्रह में अंतरराष्ट्रीय समुदाय का कोई प्रतिनिधि नहीं था। इस पर जखारोवा ने चीखते हुए पूछा कि तुमसे यह किसने कहा? तुम्हारा क्या मतलब है? संग्रह में बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक थे!

इस बीच यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस ने कई यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर हमला किया है। रूस के 24 फरवरी के आक्रमण के बाद से पश्चिम ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति बढ़ा दी है और रूस की सेना उन्हें रोकने और नष्ट करने की कोशिश कर रही है। मॉस्को का कहना है कि कीव को हथियारों की डिलीवरी और रूसी अर्थव्यवस्था के खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाना, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा प्रॉक्सी वॉर जैसा है। इससे पहले रूसी सेना ने शनिवार को कहा कि उसने यूक्रेन के जाइटॉमिर क्षेत्र में पश्चिमी हथियारों की एक बड़ी खेप को समुद्र से लॉन्च की गई क्रूज मिसाइलों का उपयोग करके नष्ट कर दिया।

अफ्रीका का साहेल क्षेत्र भुखमरी का शिकार, संयुक्त राष्ट्र बोला- 1.8 करोड़ लोगों का जीवन संकट में

जिनेवा (ईएमएस)। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया को आगाह करते हुए चेताया है कि अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में रह रहे 1.8 करोड़ लोग अगले तीन महीने में गंभीर भुखमरी की स्थिति का सामना करेंगे। विश्व निकाय ने इसके लिए यूक्रेन-रूस युद्ध, कोरोना वायरस महामारी, जलवायु परिवर्तन के असर और कीमतों में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र के एक पदाधिकारी ने बताया कि भुखमरी की वजह से प्रभावित इलाके से और लोग पलायन करने को मजबूर होंगे। मानवीय मामलों में समन्वय कार्यलय ने शुक्रवार को कहा कि बड़ी संख्या में इलाके के लोग वर्ष 2014 से ही गंभीर भुखमरी के खतरे का सामना कर रहे हैं। चार देशों, बुर्किना फासो, चाड, माली और नाइजर की चिंताजनक स्थिति है। कार्यालय के मुताबिक इन चार देशों की 1.7 करोड़ आबादी खाद्य सुरक्षा को लेकर आपात स्थिति का सामना कर रही है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रवक्ता टॉमसन फिरी ने कहा कि साहेल क्षेत्र अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में अवस्थित है और करीब एक दशक से बदतरर कृषि उत्पादन का सामना कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र ने आशंका जताई है कि गर्मी की शुरुआत में खाद्यान्न की कमी से स्थिति और खराब होगी। जिनेवा में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि निश्चित तौर पर स्थिति बेहतर होने से पहले और खराब होगी। हम देख सकते हैं कि और लोग पलायन करने की कोशिश करेंगे। इसकी बहुत संभावना है। मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत टॉमस ओजेआ क्विंटाना ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा कि सामान्य उत्तर कोरियाई नागरिक गरिमा का जीवन जीने के लिए दिन-प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि उत्तर कोरिया में लगातार बिगड़ती मानवीय स्थिति गंभीर संकट में बदल सकती है। क्विंटाना ने कहा कि गंभीर खाद्य संकट की स्थिति में उत्तर कोरिया के सबसे कमजोर लोगों की रक्षा के लिए प्रतिबंधों में शिथिलता दी जानी चाहिए।

उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे को रोकने अमेरिका, दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास को तैयार

सियोल (ईएमएस)। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की परमाणु शस्त्रों की सनक से पूरी दुनिया को खतरा है ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने शनिवार को मुलाकात के बाद कहा कि उत्तर कोरिया के साथ वास्तविक कूटनीति की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, ऐसे में वे उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे को रोकने के लिए विस्तारित सैन्य अभ्यास पर विचार करेंगे।ये घोषणा दोनों नेताओं द्वारा अपने पूर्ववर्तियों की नीति में बदलाव को दर्शाती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अभ्यास को खत्म करने का विचार किया था और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के प्रति झुकाव दिखाया था।

वहीं, दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति मून जेई इन उत्तर कोरिया द्वारा बार-बार पीछे हटने के बावजूद अपने कार्यकाल के खत्म होने तक किम के साथ वार्ता के लिए प्रतिबद्ध थे। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सहयोग 'सभी खतरों का एक साथ मुकाबला करने की हमारी तत्परता' को दर्शाता है। बाइडेन और यून ने एक संवाददाता सम्मेलन में इस बात को दोहराया कि उनका साझा लक्ष्य उत्तर कोरिया का पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने एक संयुक्त बयान जारी करके कहा कि वे यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद 'नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था' के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह बयान उत्तर कोरिया का आक्रोश और बढ़ा सकता है, जिसने अपने परमाणु हथियारों और मिसाइल विकास कार्यक्रमों का बचाव किया है, जिसे वह अमेरिकी खतरों के रूप में मानता है और लंबे समय से अमेरिका-दक्षिण कोरिया सैन्य अभ्यास को आक्रमण पूर्वाभ्यास के रूप में बताता है।

हालांकि, सहयोगियों ने अभ्यास को रक्षात्मक बताया है। बाइडेन ने एक बैठक में अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष से कहा कि दोनों देशों के बीच 70 साल का गठबंधन 'साझे बलिदान' पर आधारित है और इसे नए स्तरों पर ले जाया जाएगा क्योंकि व्यापार और प्रौद्योगिकी पर अतिरिक्त ध्यान देकर राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'दोनों देश इस समय अवसरों और चुनौतियों दोनों का सामना करने के लिए काम कर रहे हैं।' द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरियाई प्रायद्वीप के विभाजन से दो देशों का जन्म हुआ। बाइडन ने उत्तर कोरिया को टीकों की अपनी पेशकश को दोहराया क्योंकि कोरोनो वायरस देश में खतरनाक रूप से तेजी से फैल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वह किम जोंग उन से मिलने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उत्तर कोरिया के नेता 'ईमानदारी बरतें' और 'गंभीर' हों। बाइडेन ने कहा, 'हां, हमने न केवल उत्तर कोरिया को बल्कि चीन को भी टीके की पेशकश की है। हम तुरंत ऐसा करने के लिए तैयार हैं। हमें कोई जवाब नहीं मिला है।'

दक्षिण कोरिया की यात्रा पर गए बाइडेन देश में कंप्यूटर चिप्स और अगली पीढ़ी के ऑटो के लिए कारखानों का दौरा कर रहे हैं और अधिक सहयोग के लिए बातचीत कर रहे हैं। हालांकि, उत्तर कोरिया में इस वक्त बड़े पैमाने पर घातक कोरोना वायरस का प्रकोप है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने एयर फोर्स वन में सवार पत्रकारों से कहा कि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ इस बात पर चर्चा की कि आखिर उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण या मिसाइल प्रक्षेपण का कैसे जवाब देंगे। सुलिवन ने इस सप्ताह की शुरुआत में अपने चीनी समकक्ष यांग जिएची के साथ भी बात की और बीजिंग से अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उत्तर कोरिया को परीक्षण रोकने के लिए मनाने का आग्रह किया। एशिया की पांच दिवसीय यात्रा के तहत बाइडन ने शनिवार को यून के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाया जिन्होंने एक सप्ताह से थोड़ा अधिक समय पहले पदभार ग्रहण किया था।

विदेशी निवेशकों ने मई में अब तक 35,000 करोड़ के शेयरों की बिकवाली की

नई दिल्ली (ईएमएस)। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा अधिक आक्रामक ढंग से ब्याज दर में वृद्धि किए जाने की आशंका तथा डॉलर की मजबूती की चिंताओं के कारण एफपीआई ने इस महीने अब तक 35,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि की निकासी की है। इसके साथ ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा शेयरों से शुद्ध धन निकासी वर्ष 2022 में अब तक 1.63 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। बाजार के जानकारों का कहना है ?कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, मुद्रास्फीति, सख्त मौद्रिक नीति एवं अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए आगे चलकर भारत में एफपीआई का प्रवाह निकट अवधि में अस्थिर बने रहने के आसार हैं। चूंकि अमेरिका का प्रमुख बाजार कमजोर है और डॉलर मजबूत हो रहा है जिससे एफपीआई द्वारा निकट भविष्य में बिकवाली जारी रहने की आशंका है। इक्विटी बाजार से विदेशी निवेशक अक्टूबर-अप्रैल के सात महीनों में कुल 1.65 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बड़ी राशि की निकासी कर चुके हैं। हालांकि अप्रैल के पहले सप्ताह में एफपीआई शुद्ध निवेशक बन गए और बाजारों में गिरावट आने के कारण शेयरों में 7,707 करोड़ रुपए का निवेश किया। हालांकि कुछ राहत की सांस के बाद एक बार फिर वे छुट्टियों के कारण कम कारोबारी सत्र वाले सप्ताह यानी 11-13 अप्रैल के दौरान शुद्ध बिकवाल बन गए और बाद के हफ्तों में भी बिकवाली जारी रही। आंकड़ों से पता चलता है कि एफपीआई प्रवाह मई के महीने में अब तक नकारात्मक बना हुआ है और 2-20 मई के दौरान 35,137 करोड़ रुपए के शेयरों की बिकवाली की गई है। भारत के अलावा, ताइवान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस सहित अन्य उभरते बाजारों में मई में अब तक धन निकासी देखी गई है।

श्रीलंका के संविधान में 21वें संशोधन की मंजूरी के लिए आज मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा प्रस्ताव

कोलंबो (ईएमएस)। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे श्रीलंका के न्याय मंत्री ने बताया कि देश के संविधान में 21वें संशोधन मंजूरी के लिए आज मंत्रिमंडल के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रस्ताव में संकट से घिरे राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की निरंकुश शक्तियों पर लगाम लगाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मीडिया में रविवार को आई एक खबर में यह जानकारी दी गई। संविधान में 21वें संशोधन से 20 ए प्रावधान के रद्द होने की संभावना है जो 19वें संशोधन के निरस्त होने के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को असीमित शक्तियां देता है। 19वें संशोधन में संसद को राष्ट्रपति से अधिक शक्तियां दी गई थीं। 'न्यूज फर्स्ट' समाचार पोर्टल ने न्याय मंत्री डॉ. विजयदास राजपक्षे के हवाले से बताया कि इस संशोधन से दोहरी नागरिकता वाले सांसदों के लिए संसद में बने रहना असंभव हो जाएगा।

देश की अर्थव्यवस्था चरमराने के चलते इस्तीफे की मांग का सामना कर रहे राष्ट्रपति गोटबाया ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले अप्रैल 2019 में अपनी अमेरिकी नागरिकता त्याग दी थी। खबर में कहा गया है कि मौजूदा स्वतंत्र आयोगों के अलावा राष्ट्रीय लेखा-जोखा आयोग और खरीद आयोग के संबंध में भी स्वतंत्र आयोग के तौर पर संशोधन किया जाएगा। विजयदास राजपक्षे ने कहा कि संविधान में 21वें संशोधन से मौजूदा आयोग की शक्तियां और मजबूत हो जाएंगी। मंत्री ने कहा कि नए संशोधर्नी में केंद्रीय बैंक के गवर्नर की नियुक्ति संवैधानिक परिषद के तहत लाने का भी प्रस्ताव है।

गौरतलब है कि राजपक्षे परिवार ने अगस्त 2020 में आम चुनाव में भारी जीत के बाद सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। उसने राष्ट्रपति की शक्तियों को बहाल करने तथा अहम पदों पर परिवार के करीबी सदस्यों को नियुक्त करने के लिए संविधान में संशोधन किया था।

इजराइल में मंकीपॉक्स का पहला मामला सामने आया

तेल अवीव (ईएमएस)। इजराइली प्राधिकारियों ने कहा है कि विदेश से लौटे एक व्यक्ति के मंकीपॉक्स से संक्रमित होने की बात सामने आई है और वे अन्य संदिग्ध मरीजों की तलाश में जुट गए हैं। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि तेल अवीव के अस्पताल में भर्ती मरीज की हालत ठीक है। मंत्रालय ने विदेश से लौटने वाले लोगों से बुखार होने और दाने निकलने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क की अपील की है।

स्वास्थ्य मंत्रालय में जन स्वास्थ्य सेवाओं की प्रमुख शैरोन एलरो-प्रीस ने रविवार को इजराइली आर्मी रेडियो को बताया कि चिकित्सा दल मंकीपॉक्स के अन्य संदिग्ध मरीजों की पहचान करने की कवायद में जुटे हैं।

इजराइल में मंकीपॉक्स का यह मामला पश्चिम एशिया में इस संक्रमण का पहला ज्ञात मामला बताया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दुनियाभर में मंकीपॉक्स संक्रमण के करीब 80 पुष्ट मामलों और तकरीबन 50 संदिग्ध मरीजों की पहचान की है। मंकीपॉक्स संक्रमण के मामले पहले केवल मध्य और पश्चिमी अफ्रीका से संबंध रखने वाले लोगों के बीच देखे गए थे, लेकिन अब ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, अमेरिका, स्वीडन और कनाडा में भी इसके मरीज सामने आए हैं।

इनमें से ज्यादातर मरीज युवा हैं और उनके अफ्रीका की यात्रा का कोई इतिहास नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया में भी मंकीपॉक्स के मामले दर्ज किए गए हैं। मंकीपॉक्स के लिए जिम्मेदार वायरस बंदरों और अन्य जंगली जानवरों में पैदा होता है।

रूस ने फिनलैंड को गैस सप्लाई रोकी, फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के ऐलान के बाद की गई कार्रवाई

मास्को (ईएमएस)। रूस के पड़ोसी फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के ऐलान के बाद तनाव काफी बढ़ गया है। इसके बाद एक्शन में आते हुए रूस ने फिनलैंड को तत्काल प्रभाव से गैस सप्लाई रोक दी है। रूस ने बताया फिनलैंड ने रूबल में गैस का भुगतान करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सप्लाई बंद कर दी गई है। रूस के इस कदम में फिनलैंड में ऊर्जा संकट गहरा सकता है।

इतना ही नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था होने तक फिनलैंड की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ सकता है। फिनलैंड अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से भारी मात्रा में गैस खरीदता है। रूसी सरकारी गैस आपूर्ति एजेंसी गजप्राम ने कहा है कि फिनलैंड ने रूबल में भुगतान करने की मांग मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पड़ोसी देश को गैस की सप्लाई रोक दी गई है। रूस का यह फैसला फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के ऐलान के बाद आया है। विदेशों से गैस खरीदने वाली फिनलैंड की सरकारी कंपनी गैसम ने कहा है कि वे पहले से ही रूसी गैस सप्लाई को बंद करने के लिए तैयार थे। उन्होंने दावा किया कि देश में गैस की किल्लतों का प्रबंध कर लिया जाएगा और इससे आम आदमी को कोई भी तकलीफ नहीं होगी।

हालांकि, विशेषज्ञों की राय है कि बाहर से गैस आयात करने पर फिनलैंड पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने प्रतिबंधों को देखते हुए सभी गैर आयातक देशों से रूबल में भुगतान करने की मांग की थी। रूस ने कहा था कि सभी देशों की गैस खरीद करने वाली एजेंसियों को रूस के बैंक में एक अकाउंट खोलना होगा और उसी के जरिए रूबल में भुगतान किया जाएगा। हालांकि, यूरोपीय संघ ने रूस के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था। जिसके बाद रूस ने पिछले महीने बुल्गारिया और पोलैंड को गैस काट दी थी।

उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने यूक्रेन की मदद के लिए शनिवार को 40 अरब डॉलर की नई सहायता से जुड़े विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए। यह विधेयक अमेरिकी कांग्रेस में दोनों दलों के समर्थन से पारित हुआ था। विधेयक रूस के साथ जारी युद्ध के चलते अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे यूक्रेन के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अम

दक्षिण गुजरात में 25 मई से बारिश की संभावना, तापमान घटने से लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत

अहमदाबाद (ईएमएस) आगामी 25 मई से दक्षिण गुजरात के जिलों में बारिश की संभावना है 25 मई से प्री मॉन्सून एक्टिविटी शुरू होने के तहत दक्षिण गुजरात के वलसाड, नवसारी जिलों में हलकी बारिश होगी जबकि केन्द्र शासित प्रदेश दमन और दादरा नगर हवेली में सामान्य बारिश हो सकती है उस दौरान अहमदाबाद में गर्मी का पारा 41 डिग्री के आसपास रहेगा भीषण गर्मी से परेशान लोग राज्य में बारिश की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं मौसम विभाग ने इस साल मॉन्सून सामान्य रहने की संभावना व्यक्त की है मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 25 मई से गुजरात में बारिश दस्तक दे सकती है 25 मई से राज्य में प्री मॉन्सून एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और इसकी शुरुआत दक्षिण गुजरात से होगी पिछले 3 दिनों से राज्य के लोगों को गर्मी से आंशिक राहत मिली है और अगले 5 दिनों तक यही स्थिति रहेगी आगामी 25 मई को दक्षिण गुजरात में हलकी बारिश होने से राज्य में गर्मी का 2 से 3 डिग्री जितना घटेगा दक्षिण गुजरात के नवसारी और वलसाड जिलों में हलकी बारिश होगी जबकि केन्द्र शासित प्रदेश दमन और दादरा नगर हवेली में भी सामान्य बारिश होने की संभावना है उस दौरान अहमदाबाद में तापमान का पारा 41 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है स्कायमेट के मुताबिक गुजरात में मई महीने के अंत तक भीषण गर्मी का दौर यथावत रहेगा केरल में 26 मई से मॉन्सून का आगमन होगा और दक्षिण गुजरात में 10 से 15 जून के बीच मॉन्सून की दस्तक हो सकती है 15 से 20 जून के दौरान राज्य के ज्यादातर जिलों में बारिश होने की संभावना है

चोरी करके जा रहे चोर की, चोरी के रिक्शे के साथ हुई दुर्घटना, हुई मौत

अहमदाबाद : आजकल चोरी का अपराध करने वाले चोर को पुलिस और कानून से पहले प्रकृति द्वारा दंडित किया जा रहा है। ऐसी ही एक घटना अहमदाबाद में हुई है, जहां एक चोर चोरी का माल छिपाकर भाग रहा था, उस समय आरोपी का रिक्शा सड़क हादसे का शिकार हो गया। इस घटना में एक आरोपी की मौत हो गई। पुलिस ने दो अन्य फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का मामला अपने कब्जे में ले लिया है।

जानकारी के अनुसार पिछले सप्ताह अहमदाबाद के दरियापुर इलाके की एक चावल मंडी से चावल की 13 बोरी की चोरी का मामला पुलिस के संज्ञान में आया था। दरियापुर पुलिस ने अपराध की जांच करते हुए मोहम्मद आमिद सैयद और अल्ताफ सैयद को गिरफ्तार कर चोरी का चावल जब्त कर लिया है। चोरी के मामले में मोहम्मद बिस्मिल्लाह अकबर की भागीदारी भी सामने आई लेकिन चोरी के कुछ घंटे बाद ही आरोपी का रिक्शा से एक्सीडेंट हो गया जिसमें बिस्मिल्लाह की मौत हो गई। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि वारदात में इस्तेमाल किया गया रिक्शा भी चोरी का था।

चावल के बोरी की चोरी की जांच करते हुए पुलिस को सीसीटीवी में एक रिक्शा की चोरी की जानकारी मिली। रिक्शा की जांच में पता चला कि वारदात में इस्तेमाल किया गया रिक्शा नारोल इलाके से चोरी हुआ था और उसी रिक्शा में चोरी को अंजाम दिया था। इसी चोरी के रिक्शे में एक आरोपी की दुर्घटना में मौत हो गई थी। यानी एक रात में तीन अलग-अलग थानों में तीन अपराध दर्ज किए गए। वारदात में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

200 मीटर की दौड़ में राज्यभर में प्रथम आई किशोरी के घर जाकर गृह मंत्री ने शुभकामनाएं

सूरत (ईएमएस) शहर के एक रत्नकार की 70 प्रतिशत दिव्यांग बेटी ने सूरत के साथ गुजरात का नाम रौशन किया है 70 प्रतिशत दिव्यांग होने के बावजूद रिन्कु जोराराम देवासी ने खेल महाकुंभ में 200 मीटर की दौड़ में राज्यभर में पहला स्थान प्राप्त किया है गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने इस उपलब्धि के लिए रिन्कु देवासी के घर जाकर उसे शुभकामनाएं दी हर्ष संघवी ने इस संदर्भ में ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा 'सूरत की स्पेशल चाइल्ड रिंकु जब 200 मीटर की दौड़ की फाइनल में प्रदर्शन करने के लिए अहमदाबाद जा रही थी, तब बस में उसे अचानक उल्टी होने लगी फाइनल के एक दिन पहले रिंकु की हालत गंभीर थी इस स्थिति में बस में पिता के साथ सवार सहयात्री ने मानवता की सुगंध फैलाई है सूरत समेत गुजरात का नाम रौशन करने वाली रिंकु देवासी से मिलने हर्ष संघवी ने अपने व्यस्त समय से वक्त निकाला और उसके घर पहुंच कर उसे शुभकामनाएं दी गौरतलब है कि 200 मीटर की दौड़ की फाइनल में प्रदर्शन के लिए रिंकु अपने पिता के साथ अहमदाबाद जा रही थी उस वक्त रिंकु को अचानक बस में उल्टियां शुरू हो गई उस वक्त बस में सवार प्रोफेसर नवीन ने काफी मदद की दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहनेवाले प्रोफेसर नवीन ने रिंकु और उसके पिता को बस अड्डे पर सोने के बजाए अपने घर ले गए और सुबह दोनों को लेकर वह स्वयं खेल महाकुंभ में ले गए जहां रिन्कु देवासी ने 200 मीटर की दौड़ में राज्यभर में पहला स्थान प्राप्त किया इसके लिए रिन्कु के पिता जोराराम ने प्रोफेसर नवीन के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि अगर आप बस में मदद न करते तो रिन्कु ने जो परिणाम प्राप्त किया है वह मिला होता

कांग्रेस की महिला विधायक ने भरी सभा में भाजपा के लिए अपशब्द का उपयोग किया

बनासकांठा (ईएमएस) वाव से कांग्रेस की महिला विधायक गेनी ठाकोर ने भाजपा के लिए अपशब्द का उपयोग किया है कांग्रेस विधायक के इस बयान की सभी निंदा कर रहे हैं देखना होगा कि कांग्रेस गेनी ठाकोर के खिलाफ क्या कार्यवाही करती है? बनासकांठा के वाव में कांग्रेस ने जन वेदना सभा का आयोजन किया था जिसमें वाव, थराद और वडगाम के कांग्रेस विधायकों की उपस्थिति में आयोजित इस सभा में गेनी ठाकोर सरकार पर प्रहार करते हुए अपशब्दों का उपयोग किया राजनीतिक लडाई में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग अशोभनीय है राजनीतिक वार समझा जा सकता है, लेकिन जनसभा में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कितना उचित है? कांग्रेस विधायक गेनी ठाकोर ने भाजपा सरकार पर कड़े प्रहार किए और कहा कि आज चोर ही कोटवाल को दंडित करता है भाजपा सरकार की ताकत नहीं है जो जिग्नेश मेवाणी, गेनी ठाकोर या गुलाबसिंह को खरीद सके यह लड़ाई उस सरकार के खिलाफ जिसने फर्जी मुकद्दमे दर्ज किए हैं, उसे वापस लेने की लड़ाई है सरकार में अगर हिम्मत है तो जिग्नेश, गेनी और गुलाबसिंह के खिलाफ केस दर्ज करे चुनाव जीतने के लिए कंटनरों में शराब लाकर आखिर कब तक युवाओं को बर्बाद करोगे यहां से आगे बोलते हुए गेनी ठाकोर ने भाजपा सरकार के खिलाफ अपशब्द का उपयोग किया, जिसे यहां लिखा नहीं जा सकता गेनी ठाकोर ने कहा कि भाजपा शासन में राज्य की बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं हैं सभा में मौजूद लोगों से कांग्रेस विधायक ने कहा कि आपने हमें नेता के तौर पर स्वीकार किया है और हम चाहते हैं कि विभिन्न समाज के बीच मनभेद खत्म हो हमारे राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ वोटों का नुकसान भले हो, परंतु भाई-भाई के बीच भेद मत होने देना उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई वाव की भूमि से शुरू हुई है बता दें कि राजनीतिक द्वेष के खिलाफ कांग्रेस ने जन वेदना सभा का आयोजन किया था पाटीदार समाज की भांति अन्य समाज के लोगों और गेनी ठाकोर की जनता रेड के दौरान युवाओं पर दर्ज किए गए मुकद्दमे वापस लेने की मांग इस जन वेदना सभा की गई

लगातार हार से बौखलाए कांग्रेसी नेता अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं : भाजपा

अहमदाबाद (ईएमएस) बनासकांठा के वाव में हुई कांग्रेस की जन वेदना सभा को विवाद पैदा हो गया है सभा में कांग्रेस विधायक गेनी ठाकोर द्वारा अपशब्दों का उपयोग किए जाने पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया है भाजपा नेता हितेन्द्र पटेल ने कहा कि लगातार हार से कांग्रेस के प्रदेश और केन्द्रीय नेता इतने बौखलागए हैं कि अब अपने विरोधी दलों के खिलाफ अपशब्दों का उपयोग करने लगे हैं बता दें कि बनासकांठा के वाव में कांग्रेस की जन वेदना सभा का आयोजन किया गया था जिसमें वाव की विधायक गेनी ठाकोर, वडगाम से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी और थराद से कांग्रेस विधायक गुलाबसिंह ठाकोर मौजूद थे सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक गेनी ठाकोर ने भाजपा सरकार के खिलाफ घटिया शब्दों का उपयोग किया जिसे लेकर सभा में मौजूद लोगों में सुगबुगाहट शुरू हो गई गेनी ठाकोर के इस बयान की सभी निंदा कर रहे हैं भाजपा ने गेनी ठाकोर के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है भाजपा के हितेन्द्र पटेल ने कहा कि कांग्रेस लगातार हार का सामना कर रही है, जिसकी वजह से उसके प्रदेश और राष्ट्रीय नेता बौखला गए हैं इसी बौखलाहट में अपने विरोधी दलों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा उपयोग कर रहे हैं

सिटी-बीआरटीएस बस में 25 रुपये के टिकट पर पूरे दिन की असीमित यात्रा

मध्यम व मजदूर वर्ग को मिलेगी आर्थिक राहतः शहर में 58 रूटों पर बसों में 2.30 लाख लोग सफर करते हैं

सूरत : महानगरपालिका की योजना सूरत में यातायात-प्रदूषण को कम करने के लिए

शहर की यातायात समस्या को हल करने और प्रदूषण को कम करने और मध्यम और श्रमिक वर्ग को आर्थिक रूप से बचाने के लिए, सूरत नगर निगम रुपये का बस टिकट लेने की योजना बना रहा है। वर्तमान में 2.30 लाख लोग 58 विभिन्न रूटों पर दैनिक बस सेवा का लाभ उठा रहे हैं।

कोरोना काल में बस सेवा में यात्रियों की भीड़ कम होने के बाद नागरिक फिर से बस सेवा का पूरा लाभ उठा रहे हैं। सूरत पूरे देश में एकमात्र शहर है जहां कोई भी सिंगल टिकट ले सकता है और बीआरटीएस या सिटी बस में यात्रा कर सकता है। वर्तमान में शहर में 13 बीआरटीएस और 45 सिटी बसों सहित 58 रूटों पर चलने वाली बसों में रोजाना 2.30 लाख नागरिक सफर कर रहे हैं।

इस बीच, आज हुई सूरत सिटीलिंक की बोर्ड बैठक में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में डिजिटल कैशलेस लेनदेन को प्राथमिकता देने और नागरिकों का लाभ उठाने के लिए मनीकार्ड में 100 और उन लोगों के लिए एक महीने के लिए 100 प्रतिशत यात्रा छूट का लाभ उठाने का निर्णय लिया गया। सिटीलिंक मोबाइल एप से टिकट बुक करें। मध्यम वर्ग के अलावा दैनिक यात्रियों को आर्थिक रूप से बचत करने और शहर में प्रदूषण को कम करने के साथ-साथ यातायात की समस्या को भी कम करने के लिए सीटी बस और बीआरटीएस बस में 25 रुपये की टीकट लेकर पुरा दिन असिमित यात्रा की सुविधा नजदीक के भविष्य में शुरू होने जा रही है।

विभिन्न श्रेणियों में बस किराए की पेशकश की जाती है। सरल पास योजना के तहत असीमित यात्रा प्रीपेड कार्ड जारी किया जाता है। जिसमें छात्रों के लिए वार्षिक शुल्क 1000 रुपये, छह मासिक 500 रुपये तिमाही 300 रुपये है। महिलाओं के लिए 5 हजार प्रति वर्ष, 2600 रुपये छह मासिक, 1350 रुपये प्रति तिमाही और 500 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1000, छह माह के लिए 500, तिमाही के लिए 300 निर्धारित।

परिवर्तन यात्रा को मिल रहा जनसमर्थन, बहुमत हासिल करेगी आपः इटालिया

अहमदाबाद गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जनता में अपनी बैठ बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा को अच्छा जनसमर्थन मिलने का दावा पार्टी की ओर से किया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया का कहना है कि बीते एक सप्ताह से चल रही परिवर्तन यात्रा गुजरात की जनता के लिए एक उम्मीद बन गई है। परिवर्तन यात्रा को जगह-जगह से बेहतर जनसमर्थन मिल रहा है। ये दर्शाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी बहुमत हासिल करेगी। परिवर्तन यात्रा गुजरात की राजनीति बदलने का माध्यम बनेगी। सोमनाथ से प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया, प्रदेश युवा अध्यक्ष प्रवीण राम और प्रदेश उपाध्यक्ष निमिषा बेन खूंट की अगुवाई में निकली यह यात्रा दामनगर से सुबह निकलकर लाठी पहुंचीं। वहा से बाबरा पहुंची और फिर अमरेली से निकलकर रात 8 बजे सावरकुंडला में यात्रा रुकेगी। पार्टी के अन्य नेता भी अलग अलग जगह रूट पर यात्रा निकाल रहे हैं। इटालिया ने कहा कि इस परिवर्तन यात्रा के जरिए पार्टी भाजपा और कांग्रेस की मिलीभगत को जनता के सामने बेनकाब करने का काम कर रही है। परिवर्तन यात्रा के दौरान मिल रहे जनसमर्थन से साबित हो रहा है कि आम आदमी पार्टी अगले चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत हासिल करेगी। परिवर्तन यात्रा ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा से भर दिया है।

हार्दिक के राजनीतिक भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं उनके ऊपर दर्ज 23 मुकदमे

नई दिल्ली (ईएमएस)। हार्दिक पटेल ने गत 18 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीश ठाकोर ने दावा किया कि पाटीदार नेता को डर था कि उनके खिलाफ दर्ज किए गए देशद्रोह के मामलों में उन्हें जेल हो जाएगी। इसलिए उन्हें 'किसी' की शरण की जरूरत महसूस हुई। इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस से विदाई ले ली।

हार्दिक के खिलाफ क्या मामले हैं, और वे उनके राजनीतिक करियर को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? आइए विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। सन 2015 से 2018 के बीच दर्ज कम से कम 30 एफआईआर में हार्दिक को आरोपी के रूप में नामित किया गया है। इनमें से 7 मुकदमे 2015 में गुजरात में पाटीदार समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर हुए आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए थे, जिसमें दंगा और देशद्रोह जैसे कई आपराधिक अपराधों के लिए हार्दिक को आरोपित किया गया था। हार्दिक पटेल इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। पाटीदार आंदोलन में कथित आंतरिक विवादों के लिए हार्दिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

उदाहरण के लिए, सरदार पटेल समूह के तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रकाश पटेल की शिकायत पर हार्दिक के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए, अगस्त 2015 में मेहसाणा के काडी पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अन्य मामलों में 2016 में सूरत के सचिन पुलिस स्टेशन में जेल अधिनियम के तहत हार्दिक पटेल के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था। जब उन्हें अदालत की सुनवाई में पेशी के लिए विसनगर ले जाया जा रहा था, उनकी जेब से एक मोबाइल फोन चार्जर, बैटरी और पत्र की बरामदगी हुई थी। इस मामले का निपटान 2017 में सूरत जेएमएफसी द्वारा कर दिया गया था।

हार्दिक पटेल के मुताबिक फिलहाल उनके खिलाफ 23 केस चल रहे हैं। हार्दिक पटेल ने 2016 में गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष अपने खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में राहत की मांग करते हुए, शपथ ली थी कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी गतिविधि में शामिल हुए बिना, जो अपराध हो सकता है, पाटीदार समुदाय की परेशानियों को उठाते रहेंगे, और उसके निवारण के लिए सरकार का विरोध करना जारी रखेंगे। वह राज्य भर में कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करने वाले किसी भी कार्य या गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। किसी भी तरह से जनता को उकसाने वाली गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे।

लेकिन 2015 के पाटीदार आंदोलन से उपजी बाद की रैलियों और विरोध प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप 2016, 2017 और 2018 में हार्दिक के खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज हुईं। गुजरात सरकार, इसका इस्तेमाल अक्सर सजा, जमानत या किसी भी मामले में राहत के लिए हार्दिक की याचिका का विरोध करने के लिए करती है। इनमें से अधिकांश एफआईआर सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन करते हुए गैरकानूनी सभा का आयोजन या राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमति देने से इनकार करने के बावजूद रैलियां या सार्वजनिक सभा आयोजित करने से संबंधित थीं। वर्तमान में, हार्दिक को कम से कम 11 मुकदमों में अदालती कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है, जो विभिन्न चरणों में लंबित हैं, इनमें 2 मुकदमे देशद्रोह के हैं। इस संबंध में एक एफआईआर अहमदाबाद के क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में और दूसरी एफआईआर सूरत के अमरोली थाने में दर्ज है। शेष मामलों में या तो राज्य द्वारा केस वापस ले लिया गया है, या गुजरात हाईकोर्ट द्वारा केस खारिज कर दिया गया है, या फिर सक्षम अदालत द्वारा केस में फैसला सुनाया गया है, या अब तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, एक दोषी व्यक्ति तब तक चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक कि अदालत द्वारा उसकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगा दी जाती। एक मौजूदा सांसद/विधायक, अगर सीट धारण करने के कार्यकाल के दौरान दोषी ठहराया जाता है, तो उसे सजा के फैसले की तारीख से 3 महीने के अंदर सीट से अयोग्य घोषित किया जा सकता है, जब तक अपीलीय अदालत दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाती। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सितंबर 2020 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अन्य अदालतों को मौजूदा या पूर्व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामलों पर तेजी से निर्णय लेने का निर्देश दिया था, हार्दिक के खिलाफ लंबित मामले उनकी चुनावी संभावनाओं पर लटकती तलवार की तरह हैं।

गुजरात में जातिगत गठजोड़ में जुटी कांग्रेस, ओबीसी और पाटीदार समुदाय पर खेलेगी दांव

अहमदाबाद। गुजरात में कांग्रेस पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की भरपाई खोडलधाम ट्रस्टी नरेश पटेल से करने की तैयारी में है। प्रदेश प्रभारी रघु शर्मा ने गत दिनों नरेश भाई से मिलकर उन्हें पार्टी आलाकमान के निर्णय से अवगत करा दिया। अब फैसला नरेश पटेल को करना है। कांग्रेस इसे जिताऊ फार्मूला मान रही है।कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर के बाद हालांकि गुजरात में कुछ बदलता नजर नहीं आ रहा। लेकिन पार्टी के पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए पूर्व अध्यक्ष अमित चावडा, पूर्व नेता विपक्ष परेश धनाणी समेत सात सदस्यों की समिति का गठन किया गया है। विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस ओबीसी, दलित, पाटीदार व अल्पसंख्यक समुदाय पर दांव खेलेगी। यह रणनीति पूर्व मुख्यमंत्री माधवसिंह सोलंकी की खाम (क्षत्रिय, दलित, आदिवासी और मुस्लिम) थियरी जैसी ही है। वर्ष 1985 में कांग्रेस ने इस समीकरण से रिकार्ड 149 सीट जीत ली थी।

कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले हार्दिक पटेल कहते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1984 में हत्या के कारण सहानुभूति लहर से यह रिकार्ड जीत हुई। अन्यथा अगले ही चुनाव में खाम थियरी ढेर हो गई थी। पाटीदार आंदोलन में हार्दिक के साथी और नरेश पटेल के करीबी दिनेश बामणिया का मानना है कि नरेश भाई कांग्रेस से ही राजनीतिक पारी शुरू करेंगे, अन्यथा राजनीति से ही दूर रहेंगे। खोडलधाम की जिम्मेदारी के चलते नरेश पटेल फैसला नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल सिंगापुर की यात्रा पर हैं। सोमवार को लौटकर शायद वे इस संबंध में कोई एलान करें।

कांग्रेस ने उदयपुर चिंतन शिविर के बाद एक समिति बनाई है, जो पार्टी के पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगी। विधायकों व पदाधिकारियों में कौन सक्रिय हैं और कौन नहीं, इस रिपोर्ट के आधार पर ही पार्टी टिकट का भी फैसला करेगी। प्रभारी डा रघु शर्मा का कहना है कि चिंतन शिविर के फैसले गुजरात में जल्द लागू होंगे। कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नरेश पटेल के संबंध में कहा कि पार्टी में आने का फैसला उनको करना है। माना जा रहा है कि गत दिनों मिलकर उन्होंने कांग्रेस आलाकमान का प्रस्ताव नरेश भाई के समक्ष रख दिया है, जिसमें उन्हें चुनाव प्रचार अभियान का चेहरा बनाने की सबसे अधिक संभावना है। इस पद पर गत चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला की नजर थी। हाल में हार्दिक पटेल भी कुछ ऐसी ही जिम्मेदारी का दबाव बना रहे थे।

विधानसभा चुनाव निकट देख केन्द्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाईं : कांग्रेस

वडोदार (ईएमएस) गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा ने केन्द्र सरकार पर आज आरोप लगाया कि उसने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कटौती की है उन्होंने कहा कि हम भाजपा को लोगों के बीच एक्सपोज करेंगे रविवार को वडोदरा में मध्य जोन की बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें मध्य जोन कांग्रेस के सभी पदाधिकारी शामिल हुए और आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की इस मौके पर रघु शर्मा ने कहा कि आगामी चुनाव में गुजरात कांग्रेस ने 125 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है राहुल गांधी ने दाहोद से आदिवासी सत्याग्रह कार्यक्रम शुरू किया है राज्य के चार मंडलों में होनेवाले कार्यक्रमों में राहुल गांधी भी शामिल होंगे आगामी चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस की ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में एक्साइज डयूटी घटाने के केन्द्र के फैसले को चुनावी बताया साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकारों को पेट्रोल-डीजल पर वेट घटाना चाहिए सरकार ने पहले पेट्रोल-डीजल के कीमतें बढ़ाई और अब चुनाव निकट आते ही इसकी कीमतों में मामूली कटौती की है गुजरात कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख जगदीश ठाकोर ने आगामी चुनाव में जीत का दावा करते हुए किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करने से इंकार कर दिया उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में हमारा लक्ष्य 125 सीटें जीतने का है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जिगदीश ठाकोर ने कहा कि नरेश पटेल को कब कांग्रेस जॉइन करनी है इसका फैसला उन्हें ही करना है

बाल्टी और मटके लेकर पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मनपा कार्यालय

शहर में एक ओर भीषण गर्मी पड़ रही है वहीं दूसरी ओर लोगों को पर्याप्त और शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल रहा है। शहर के कई इलाकों में टेंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है। इन समस्याओं को लेकर कुछ दिनों पहले मनपा आयुक्त आवास पर प्रदर्शन करने के बाद अहमदाबाद मनपा मुख्यालय पर हल्लाबोल किया।

बाल्टी और मटके लेकर पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मनपा कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया गया। प्रवेश द्वार पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे इसके चलते कार्यकर्ता नाराज हो गए। मनपा मुख्यालय के बाहर काफी देर तक ट्रैफिक जाम हो गया। दरअसल जिस समय ये सभी कार्यकर्ता नेता प्रतिपक्ष शहजादखान पठान की अगुवाई में प्रदर्शन करने और ज्ञापन देने पहुंचे थे उस समय मनपा कार्यालय में महापौर सहित अन्य पदाधिकारी नहीं थे। वे चांदखेड़ा व अन्य वार्ड में कार्य?मों में थे। इसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रवेश नहीं दिया गया। इस पर वे भडक गए। उन्होंने गेट पर चढकर और गेट के सामने ही प्लास्टिक की बाल्टी व मटकों को तोडकर अपना विरोध व्यक्त किया। शहजादखान का आरोप था कि मनपा प्रशासन इतने सालों में भी लोगों को पीने का शुद्ध और पर्याप्त पानी देने में विफल रहा है।

बिजली के दामों में वृद्धि हुई तो करेंगे जन आंदोलनः गढवी

अहमदाबाद. गुजरात आम आदमी पार्टी के नेता इसुदान गढवी ने सहा कि एक तरफ दिल्ली में 200 यूनिट बिजली पर 0 बिल आता है। पंजाब में 300 यूनिट बिजली पर भी 1 जुलाई से 0 बिल आएगा। तो दूसरी तरफ गुजरात के भाजपा शासन में बार-बार बिजली के दामों में बढ़ोतरी करके सरकार ने जनता का जीना मुश्किल कर दिया है।

गुजरात में वापस बिजली के दामों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके भाजपा सरकार ने अपने विफल शासन की पोल खुद ही खोल दी है। गढ़वी ने कहा कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने देश के हर राज्य में सरकारी बिजली संयंत्रों और निजी बिजली संयंत्रों को बिजली उत्पादन के लिए आयातित कोयले को 30 प्रतिशत तक मिलाकर बिजली पैदा करने को कहा है। इससे और बिजली के दामों में 5-10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना है।

गुजरात में राज्य के स्वामित्व वाली चार बिजली वितरण कंपनियों को अपने शुल्क में प्रति यूनिट 10 प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जिससे फिर से जनता पर मार पड़ेगी। लिग्नाइट सस्ता विकल्प, पूरी क्षमता से नहीं चल रहे संयंत्रः गढ़वी ने कहा कि गुजरात में कोयले से सस्ता लिग्नाइट है। लिग्नाइट के इस्तेमाल से सस्ती बिजली पैदा हो सकती है।

लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए आगामी चुनाव में सरकार बदलना जरूरी : कांग्रेस

बनासकांठा (ईएमएस) कांग्रेस विधाक शिव भूरिया का कहना है कि ईवीएम गलत नहीं होते, बल्कि हम कमल का बटन दबा देते हैं लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए आगामी चुनाव में सरकार बदलना जरूरी है बनासकांठा जिले के वाव में कांग्रेस की ओर से जन वेदना सभा का आयोजन किया गया था सभा को संबोधित करते हुए बनासकांठा के दियोदर से कांग्रेस विधायक शिव भूरिया ने कहा कि चुनाव आते ही बैठकों को दौर शुरू हो जाता है, लेकिन मतदान के दौरान कमल का बटन दबा दिया जाता है, जिसकी वजह से भाजपा की सरकार आती है चुनाव में हार का ठीकरा हमेशा ईवीएम पर फोड़ते हैं, जबकि ईवीएम में कोई दोष नहीं है दोष हममें है जो कमल चिह्न का बटन दबा देते हैं इसलिए आगामी चुनाव में जागृत होकर देश में लोकतंत्र को जीवित रखना है तो सरकार बदलें शिव भूरिया ने आगामी चुनाव में थराद और वाव सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के जीतने की उम्मीद व्यक्त की

कार से नशा का जत्था जब्त, 308 बोतल विदेशी शराब और बीयर जब्त

पुलिस ने 30,000 रुपये से अधिक की शराब और 30,000 रुपये की नैनो कार जब्त की

सूरत : पुलिस ने आरोपी को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू की

सूरत से एक बार फिर पुलिस ने शराब का जत्था जब्त करने में सफलता हासिल की है। उधना पुलिस ने भारतीय निर्मित अंग्रेजी शराब की 308 बोतल और बीयर का टिन जब्त किया है। पुलिस ने 30,000 से अधिक कि शराब और चौपहिया वाहन 30,000 सहित कुल 60,000 से अधिक माल सामान जब्त किए हैं।

उधना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नैनो कार की जांच की। पुलिस ने कार से 308 बोतल विदेशी शराब और बीयर बरामद की। ईडब्ल्यूएल आवास भेस्तान सूरत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।

परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री हार्दिक रत्न सुरीस्वरजी महाराज साहब (जैन साधु भगवंत) द्वारा जैन साधुनी हिमालय यात्रा का विमोचन

90 दिनों में पूरी की 2000 किलोमीटर की हिमालय यात्रा

इस पुस्तक में वर्णित 100 से अधिक अनसुने पौधे

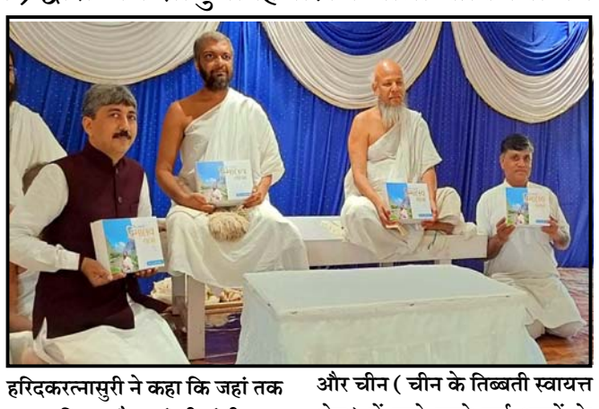

अहमदाबाद, 8 मई, 207: परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री हरिदकरत्नासुरी ने हाल ही में 6000 किलोमीटर हिमालय की यात्रा की। यह यात्रा इतिहास में पहली बार जैन महाराज साहेब द्वारा की गई है, जिनका मुख्य उद्देश्य लोगों को अंतरधार्मिक सद्भाव और प्राकृतिक सुंदरता के पूर्ण क्षणों से अवगत कराना है। हिमालय के प्रेमियों को यह ट्रेक कितना कठिन, सुंदर और अविस्मरणीय है, इसके हर पल और हर पल का अनुभव कराने के लिए उन्होंने ठजैन साधु की हिमालय यात्राठ पुस्तक पेश की है। जिसे आज श्री झालावाड़ समाज ट्रस्ट हॉल, पालड़ी में मीडिया के सामने जारी किया गया। कार्यक्रम का आयोजन परम गुरु भक्त श्री चंद्रेशभाई शाह (ट्रस्टी-श्री सिद्धचलशंगर जैन ट्रस्ट एवं मंगल अरिहंत सिद्धाचल धाम जैन ट्रस्ट अधिद्वीप-पालिताना) द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री रमेशभाई तन्ना (लेखक, सकारात्मक कहानी) विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

इस अवसर पर उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री हरिदकरत्नासुरी ने कहा कि जहां तक नजारा दिखता है, वहां की ऊंची सतह पर स्थित दर्शनीय क्षेत्र देखने योग्य होता है क्योंकि तीर्थयात्री प्राकृतिक सौंदर्य के बीच चट्टानों से बाहर निकलते हैं। इस क्षेत्र का चट्टानी चेहरा स्पष्ट रूप से काला है, लेकिन इसका शिखर सफेद बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ है। इसके पिघलने वाले हिमनद सामने की भूमि की विशाल झीलों में बह रहे हैं। इसके जल की पवित्रता, शुद्धता और सुंदरता अवर्णनीय है। जिसे हमने इस पुस्तक में फोटो और टेक्स्ट के साथ प्रस्तुत किया है।

भिक्षुओं, संतों, लामाओं, जापानी, बौद्धों, हिंदुओं और जैनियों, आध्यात्मिक प्राणियों की उपस्थिति के कारण इस भूमि का सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व सदियों से बरकरार है। भारत, नेपाल, भूटान और चीन (चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र) में रहने वाले कई भक्तों के लिए, यह क्षेत्र भगवान शंकर और देवी पार्वती सहित देवी-देवताओं का घर है। इसलिए जीवन में एक बार कैलाश-मानसरोवर की यात्रा करना महत्वपूर्ण माना जाता है। यात्रा दो से तीन सप्ताह तक चलती है। (यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करते हैं।) .. लेकिन हमारी यात्रा बहुत सुंदर और 90 दिन लंबी थी। जिसमें हम 4 महाराज साहब शामिल हुए।

इस किताब को पढ़ने